महामन्त्री

का

प्रतिवेदन

भारतीय मजदूर संघ

६ठाँ अखिल भारतीय अधिवेशन

कलकत्ता

दिनांक ७ व ८ मार्च, १९८१

-रामनरेश सिंह

प्रतिनिधि बन्धुओं एवं भगिनियों,

मैं इस प्रतिवेदन को आपकी सेवा में विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

रामनरेश सिंह
महामन्त्री

●

भारतीय मजदूर संघ

महामंत्री का प्रतिवेदन

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मा० श्री ठेंगड़ी जी, श्रद्धेय अभ्यागत वृन्द तथा बन्धुओं व भगिनियों !

भारतीय मजदूर संघ के रजत जयन्ती वर्ष में आयोजित ६ठे राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर 'नृपेन्द्र नगर' में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

देश, धर्म व भारतीय संस्कृति के उन्नयन हेतु सर्वस्व अर्पित करने वाले रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस, राजा राममोहन राय, डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा खुदीराम बोस, सूर्यसेन, प्रफुल्लचाकी, जतीनदास प्रभृति जैसे अनेक बलिदानियों, सन्यासियों व समाज सुधारकों की जन्मभूमि बंगाल मे आप जैसे प्रखर राष्ट्रभक्तों व भारतीयता के पुजारियों का एकत्रीकरण एक विशेष महत्व रखता है, यद्यपि इधर कुछ वर्षों से दारिद्रय, वेरोजगारी व अभावों के कारण यहां के मजदूर कुछ अंशों में विदेशी विचारधारा की ओर आकृष्ट हुए हैं। किन्तु हमारा यह निश्चित विश्वास है कि वे भी देश की मूल धारा के साथ समरस होकर चलने में अब देर नहीं करेंगे।

यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि इस वर्ष महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुयी है। हमें यह आशा है कि वे भी उत्साहपूर्ण संदेश लेकर वापस लौटेगीं तथा कार्य बढ़ाने में अधिक योगदान करेंगी।

मजदूर क्षेत्र की दृष्टि से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से अप्रैल ७८ में सम्पन्न हुये जयपुर अधिवेशन के पश्चात् के ये ३ वर्ष पूरे रूप से आच्छादित हैं। इन सबको आपके सम्मुख रखने के पूर्व जो आज हमसे बिछुड़ गये

हैं, ऐसे अनेक महानुभावों, साथियों एवं कार्यकर्ताओं को अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना उचित होगा।

हम अपने प्रथम अध्यक्ष (१९६७-७०) श्री दादा साहेब काम्बले (कामटी विदर्भ) के पितृवत नेतृत्व से वंचित हो चुके हैं। उन्होंने डाक-विभाग में नौकरी करते हुये मजदूर संगठनों में काम किया और नेतृत्व किया तथा निवृत्ति होने के पश्चात् भी भारतीय मजदूर संघ के कार्य को मृत्यु-पर्यन्त करते रहे। उनकी मृत्यु से भारतीय मजदूर संघ को अपार क्षति हुयी है।

लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण का सम्पूर्ण जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में ही बीता। अवसर सुलभ होने पर भी सत्ता के गलियारे में प्रवेश करने की उन्होंने किन्चित भी अभिलाषा नहीं की। वर्तमान युग के लिये उनका यह अनुपम आदर्श सभी के लिये अनुकरणीय है। 'राजनीति' के बजाय 'लोकनीति' को स्वीकार किया। आपातकाल के बर्बर दमन के विरोध का नेतृत्व किया। मजदूर आंदोलन की प्रारम्भिक अवस्था से ही वे जुड़े थे। रेल मजदूरों के लिये उनके द्वारा की गई सेवायें मजदूर आन्दोलन के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। देश की जनता ने न केवल अपने लोकप्रिय नेता को गँवाया, अपितु लोक नायक को ही खो दिया है।

श्री वाराह वेंकट गिरी आज हमारे बीच नहीं हैं। एक मूर्धन्य मजदूर नेता से एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुये वे राष्ट्रपति के उच्चतम पद तक पहुंचे। वे सत्ता से दूर रहे अथवा सत्ता में-सदैव मेहनतकश जनता के सच्चे मित्र रहे। जीवन के अन्तिम क्षण तक 'एक उद्योग में एक यूनियन' के विचार तथा उस स्थिति के निर्माण होने तक 'सामूहिक सौदेबाजी' के प्रमुख हिमायती के रूप में हम उनका सदैव स्मरण करते रहेंगे।

विदेश के स्वर्गवासी हुए महानुभावों में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का नाम स्मरणीय है। उन्होंने अपने देश को एक ओर जर्मन नाजियों से स्वतन्त्र किया, दूसरी ओर स्वयं एक कट्टर साम्यवादी होते हुये भी स्टालिन जैसे निर्दयी तानाशाह से लोहा लेकर साम्यवादी खेमे से भी स्वतन्त्र रखा। निर्गुट आन्दोलन के प्रवर्तकों में से वे एक थे। यूगोस्लाविया में मजदूरों के स्वामित्व में मजदूरों की समितियों द्वारा संचालित उद्योगों की प्रचलित अनोखी सामाजिक आर्थिक जीवन पद्धति के विकास में उनका योगदान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

ए० एफ० एल०-सी० आई० ओ० अमेरिका के प्रसिद्ध मजदूर नेता जार्ज

की मृत्यु से विश्व के मजदूर आन्दोलन की अपार क्षति हुई है। इन्होंने अपने देश में ट्रेड यूनियन कार्यक्रमों में प्रार्थना की पद्धति चलाकर एक स्वस्थ एवं स्फूर्तिदायी परम्परा का निर्माण किया है।

इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनेक समर्पित नेता काल कवलित हो गये। भूतपूर्व सरकार्यवाह सर्वश्री मा० अप्पा जी जोशी व माधवराव मुले, पं० रामनारायण शास्त्री, भैय्या जी सर्राफ, केशव चन्द्र चक्रवर्ती तथा काशीनाथ पंत लिमये आदि ने महत्वपूर्ण पदों को सम्हालते हुए भारत माता की सेवा की है।

श्रमिक संगठनों के नेता तथा विविध क्षेत्रों के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस अवधि में काल के ग्रास बन चुके हैं। हिन्द मजदूर सभा के अध्यक्ष श्री वेंकटराम, श्रीमती मणिबेन कारा, भारतीय मजदूर संघ के श्री रजनी मुखर्जी, एटक के श्री मिरजकर व पी० सी० जोशी, सीटू के श्री दिनेन भट्टाचार्य व जीराल्ड पेरियर, ए० आई० आर० एफ० के श्री प्रिय गुप्ता, हिन्द मजदूर सभा के श्री माखन चटर्जी, भूतपूर्व केन्द्रीय श्रममन्त्री आर० के० खाडिलकर, श्री के० टी० सुले तथा अर्जुन अरोड़ा व गणेशदत्त वाजपेयी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

टाटा इन्स्टीच्यूट आफ फाउन्डेशन रिसर्च के डा० एस० डी० पुणेकर, इतिहासकार श्री आर० सी० मजूमदार, श्री चन्द्रभान गुप्त, निरन्कारी सन्त बाबा गुरबचनसिंह, भूतपूर्व रेलमन्त्री सर्वश्री हनुमंतैय्या व डा० रामसुभगसिंह, जनरल टी० एन० रैना पत्रकार शमीम अहमद शमीम, मराठी साहित्यकार श्री अनन्त काणेकर, एन० सी० फड़के, जी० डी० मादगुलकर, हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रायकृष्णद स, प्रसिद्ध सायर साहिर लुधियानवी पार्श्व गायक श्री मुहम्मद रफी, वेद पण्डित श्री श्रीकृष्ण वामन देव, श्री महाबीर त्यागी, प्रख्यात विधिवेत्ता एन सी. छागला तथा संजय गांधी आदि को हम खो चुके हैं।

हम अपने सहयोगियों में से पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के श्री इन्द्रनारायण झा, मध्य रेलवे के श्री मगेश बागले, बहादुरगढ़ के श्री ओंकार प्रसाद गुप्त, भिवानी के श्री बालकृष्ण गुप्ता, गोरखपुर के श्री सुधीरसिंह, कानपुर के श्री यज्ञदत्त शर्मा, शाहजहांपुर के श्री लवकुशसिंह, वेदप्रकाश ग्रोवर व मुहम्मद इस्लाम (कलकत्ता), गुन्टूर के श्री सूर्यनारायणा, माहे के श्री श्रीधरन व रवीन्द्रन सहित केरल में अनेक बन्धु सीटू व मार्क्सवादियों के गुण्डागर्दी के शिकार हुए, अब हमारे बीच नहीं हैं।

मजदूर विरोधी तत्वों द्वारा भड़काये जाने के फलस्वरूप गुजरात प्रदेश

मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री हसमुख भाई दवे के परिवार के ३ सदस्यों की जघन्य हत्या जैसी हृदय विदारक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है।

प्राकृतिक प्रकोपों दुर्घटनाओं तथा फरीदाबाद, कलकत्ता, बंगलोर व मोदीनगर आदि कई स्थानों पर पुलिस की गोलियों से अनेक बन्धुओं की मृत्यु हुयी है।

इस अवसर पर हम इन सभी महानुभावों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं।

राजनीति के बदलते रंग

३० वर्षों की अक्षुण्ण सत्ता के पश्चात् इन्दिरा कांग्रेस की हार तथा जनता पार्टी का उभर कर सामने आना-यदि एक महत्वपूर्ण घटना है तो १९८० में हुआ सत्ता परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जायेगा। १९८० के मध्यावधि चुनाव में जनता ने कांग्रेस आई को फिर से सत्ता पर बिठाया। जनता पार्टी की हार तो पहले ही सुनिश्चित हो गयी थी। कई पार्टियों के भानमती के कुनबे द्वारा शासन चलाये जाने का यह अनोखा प्रयोग अधिक दिन तक नहीं चल सका—यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। किन्तु उसका अन्त जितना आकस्मिक था, वह अवश्य ही विस्मयकारी एवं दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।

फिर भी जनता पार्टी के लिये यह गौरव है कि उसने अपने छोटे से कार्य-काल में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम कराने तथा आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में सफल हुई। विगत डेढ़ वर्षों की आकाश चूमती महंगाई, मुद्रा-स्फीति तथा गिरती हुयी शान्ति व्यवस्था व सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए जनता पार्टी की उपलब्धियां और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आज की स्थिति को देखकर कोई भी उस शासन को साधुवाद देगा।

विश्व राजनीति की घटनायें

अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रूस द्वारा खुल्लमखुल्ला किया गया आक्रमण तथा उसका वहाँ पर वर्ष भर से भी अधिक समय तक जमे रहना-भारत को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इससे पाकिस्तान को शस्त्र सज्जित करने के अमेरिकी प्रयास पुनर्जीवित हुये हैं और शीत युद्ध ने पुनः हमारे दरवाजे पर दस्तक देना प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी हमसे सीधा सम्बन्ध रखने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि दोनों गुटों के द्वारा हिन्द महासागर में नैवी शक्ति के अड्डे निर्माण करने के प्रयास ने इस क्षेत्र की शान्ति के लिये भीषण खतरा उत्पन्न कर दिया है।

इरान–इराक युद्ध

विश्व के दो तेल मालिक देशों-इरान व इराक का युद्ध दुनियां के अनेक देशों को प्रभावित किया है। दोनों देशों के आयल रिफाइनरीज के नष्ट होने व तेल भेजने के मार्ग अवरुद्ध होने से अनेक देशों को तेल प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हुयी है। भारत भी इस दुष्प्रभाव के चपेट से अछूता नहीं बचा है, उसके कारण हमारा आर्थिक स्थिति पर भी दुष्परिणाम हुआ है।

पेट्रो डालर की ललक

तेल उत्पादक देशों में धन कमाने की विशेष तमन्ना उत्पन्न हुयी है। उन्होंने थोड़े ही समय में पेट्रोलियम के मूल्य बढ़ाकर दुनिया की आर्थिक स्थिति में गिरावट ला दी है। अस्तु हमारे देश के लिए यह आवश्यक है कि वह ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अन्य विकल्प ढूढ़ें।

मजदूर आन्दोलन की अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें

कम्युनिस्ट शासित पोलैण्ड में उभर कर सामने आयी 'सालिडरीरी'-स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन की स्थापना निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने साम्यवादियों के इस दावे का पर्दाफाश कर झुठला दिया है कि उन देशों में ट्रेड यूनियनें स्वतन्त्र रह सकती हैं। अपने नेता श्री लेच वालेस के नेतृत्व में पोलैण्ड के मजदूरों ने यह आवाज उठाई कि 'मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार एवं पार्टी द्वारा डाली गयी बेड़ियों के अलावा तुम कुछ नहीं खो सकते।'

गैर साम्यवादी सरकारों के रहते प्राप्त स्वतन्त्रता का उपयोग कर लोगों को भड़काते रहने की ही नीति वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की रहती है और उनके नारों में भ्रमित लोगों को होश तब आता है जबकि वे न केवल अपनी स्वतन्त्रता ही खो देते हैं, बल्कि परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़ भी दिये जाते हैं।

पोलेटेरियट या वेतन भोगियों को ही साम्यवादी सरकारों में सत्ताधिष्ठित होने की घोषणा की जाती है, किन्तु पोलैण्ड की अभावग्रस्त जनता, दयनीय आर्थिक दुव्यवस्था तथा सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली अय्यासी की सुविधाओं के

विरुद्ध पोलैण्ड के मजदूरों द्वारा उठायी गयी आवाज ने दुनिया के सामने इनकी पोल खोल दी है।

पोलैण्ड के उन बहादुर मजदूरों को भारतीय मजदूर संघ बधाई देता है। पुनः वह घोषणा करता है कि मजदूर एकता एवं मजदूर आन्दोलन कि स्वतन्त्रता हेतु चलाये गये उनके संघर्ष में भारतीय मजदूर संघ का पूरा समर्थन है। यह सुखद सयोग है कि उक्त ये दो ही बातें भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा के आधार हैं।

रूस और चीन का मजदूर आज अशांत है। स्थान-स्थान से संघर्ष एवं हड़तालों के समाचार मिल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मजदूरों की आवाज को बहुत दिनों तक दबाकर रखना साम्यवादी शासकों के लिये भी सम्भव नहीं है और यह भी सिद्ध हुआ है कि कम्युनिज्म पूरी तरह असफल हुआ है। पश्चिमी जर्मनी से यह सुखद समाचार मिला है कि मालिकों द्वारा मजदूरों की प्रबन्ध में भागीदारी के कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत दावे का फैसला मजदूरों के पक्ष में हुआ है।

कई गैर साम्यवादी देशों में भी मजदूरों का दमन किया जा रहा है। मजदूर और उसके नेता बिना मुकदमा के जेलों में ठूसे जा रहे हैं। ऐसी घटनायें लेटिन अमेरिकन देशों में अधिक हो रही हैं। भारतीय मजदूर संघ इन सभी मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करता है।

रंगभेद की अमानवीय व घृणित नीति के विरुद्ध उनके सघर्ष में देशभक्त दक्षिण अफ्रीकियों का भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है।

आर्थिक दशा—

देश के सम्मुख आर्थिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। मुद्रा-स्फीति की भयानक स्थिति है। विगत सभी मानदण्डों को लांघकर वस्तुओं के मूल्य आकाश छू रहे हैं। दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का बहुत बड़ा अभाव है। वितरण प्रणाली भी दोष पूर्ण एवं भ्रष्ट है। उचित मूल्य की दुकानों पर ग्राहक की लम्बी कतारें दिखाई देती हैं। मिट्टी के तेल के लिये अन्तहीन कतारें लगती हैं। सरकार इसके लिए तेल उत्पादक देशों की तेल मूल्य वृद्धि-नीति को जिम्मेवार ठहराती है किन्तु यह बात तर्क युक्त नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता को देखकर उद्योग पतियों, व्यापारियों, बिचौलिये एवं उच्च अधिकारियों ने सामूहिक रूप से

समाज व अन्य वर्गों की घोर उपेक्षा करते हुए इन परिस्थितियों से लाभ उठाने का षड़यन्त्र रचा है। भ्रष्ट राजनैतिक नेता भी जलती हुई आग में अपनी रोटी सेंकने में पीछे नहीं हैं। सत्ताधारी दल भी लाभ उठाने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर एक ऐसी भयावह स्थिति का निर्माण हुआ है, जिसका कोई अन्त नहीं है।

सत्ता के एक वर्ष के दौरान ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार मूल्य सूचकांक में प्रत्येक मास औसत ३ अंको की दर से वृद्धि हुई है। यही सूचकांक वर्ष १९७८ में प्रत्येक मास औसतन १ अंक की दर से कम था।

उपरोक्त अनियन्त्रित लूट से सर्वत्र असन्तोष एवं बेचैनी को बढ़ावा मिला है। श्रमिकों को विवश होकर आन्दोलन की राह पकड़ना पड़ा है। असन्तुष्ट अधिकारी भी संघर्ष पथ पर हैं। लगभग सभी प्रदेशों में किसान आन्दोलन के कारण नई दिशायें खुली हैं। विद्यार्थी विद्रोह पर उतारू हैं। डाक्टरों ने संघर्ष का विगुल बजा दिया है। पुलिस व गुप्तचर संगठन भी संघर्षरत हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार नाम मात्र की तथा अकर्मण्य सरकार है।

सरकार ने यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों आदि से अपने को लैश कर लिया है फिर भी शायद ही कभी इन अधिनियमों का उपयोग मुनाफाखोरों, काला बाजारियों, तस्करों अथवा असामाजिक तत्त्वों के विरुद्ध किया गया हो। लेकिन सरकारी कर्मचारी नेताओं पर हिमांचल प्रदेश में, विद्यार्थी नेताओं पर आसाम में किसान नेताओं पर तमिलनाड में राजनेताओं पर गुजरात में तथा ट्रेड यूनियन नेताओं पर बिहार में इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है। यह समय की मांग है कि सरकार अपनी विफलताओं, कमी व दोष के लिये बहाने बाजी करते हुए बलि का बकरा न ढूँढ़ कर कोरे नारेबाजी से हटकर अपने दायित्व का निर्वाह करे।

औद्योगिक मोर्चे पर भी प्रगति के कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में आपस में ही तालमेल नहीं है। उदाहरणार्थ उर्जा शक्ति, विद्युत एवं रेलवे में प्रशासनिक अवरोधों के कारण ही उत्पादन छिन्न-भिन्न होता जा रहा है।

बिजली में निरन्तर कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अच्छे मौसम के बावजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स देश की आवश्यकताओं

की पूर्ति करने में असफल रहे हैं। पावर कट, लोड शेडिंग एवं बिजली का बार-बार चला जाना आज जीवन का एक सामान्य अंग हो गया है।

कोयला उत्पादन तथा उसके ट्रांसपोर्टेशन के बीच कोई सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण उद्योगों को कोयला नहीं पहुँच पा रहा है। लोहे और स्टील पर आधारित लघु उद्योग कच्चे माल के अभाव में निरन्तर घाटा उठा रहे हैं। सीमेन्ट का न मिलना भवन निर्माण उद्योग को प्रभावित कर रहा है। अन्य व्यवसाय की तुलना में चोर बाजारी एक अच्छा व्यवसाय बन गया है।

इन सब कारणों से उद्योगों में तालाबन्दी, बन्दी और हड़तालें हुई हैं। उदाहरणार्थ मद्रास की सबसे पुरानी मिल बी० एण्ड सी०, जिसके बन्द होने के कारण १३ हजार कर्मचारी बेकार हुए तथा भिवानी की टी. आई. टी मिल के वीविंग विभाग की बन्दी—ऐसी अनेक घटनाएं हैं।

समाज के सबसे कमजोर वर्ग को उठाने को कौन कहे इसके विपरीत भारत सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष १९८०-८१ में उद्योग एवं व्यवसाय को सभी प्रकार के सहयोग एवं प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है। अब प्रधान मन्त्री एवं वित्त मन्त्री कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने सभी सुविधाओं का सही उपयोग नहीं किया है। और अब वे रोजगार देने में भी पूर्णतया विफल हैं। वित्त मन्त्री श्री आर वेंकट रमन ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि समाज अभाव एवं बढ़ते मूल्यों के साथ लम्बी अवधि तक रहने की अपनी आदत बनाये तभी उसका गुजर हो सकता है।

बाँचू समिति की रिपोर्ट को लागू करने को कौन कहे सरकार ने कालेधन को वैधानिक बनाने के लिये जो विशेष बाण्ड योजना का निर्णय लिया है वह निश्चय ही एक गलत प्रथा को प्रोत्साहित करेगा।

सर्वत्र घोर असन्तोष व्याप्त है। वर्तमान सरकार से जनता असंतुष्ट है। शासक दल सभी प्रकार से भ्रष्ट लोगों का एक जमघट है। न कोई आदर्श है और न कोई सिद्धान्त यह तो असामाजिक एवं साम्प्रदायिक लोगों के लिये स्वर्ग बन गया है। शासक दल में कोई कैडर नहीं है—यह तो अवसरवादियों की एक जमात है, जो मात्र एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। जहां सत्ताधारी दल की यह दशा है वहीं सत्ताधारी दल का कोई विकल्प भी नजर नहीं आता है। विरोधी पक्ष भी हताश है। सभी योग्य सिद्धान्त, एव मान्यताएं छोड़ चुके हैं।

विरोधी पक्ष भी इससे लाभ उठाना चाहते हैं। जन साधारण में व्याप्त असन्तोष का वे नकदीकरण करना चाहते हैं। वे अधिक से अधिक अराजकता एवं असन्तोष निर्माण का लक्ष बनाये हुए हैं, जो देश के लिये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा।

भारत सरकार की श्रम नीति

कांग्रेस सरकार ने अभी भी अपनी श्रम-नीति स्पष्ट नहीं की है, किन्तु जो कुछ उसने किया है, उससे भी श्रमिकों को आशान्वित होने की स्थिति नहीं बनती।

इस एक वर्ष में केन्द्रीय श्रम मन्त्री बार-बार बदल जाते रहे हैं। वर्तमान श्रम मन्त्री भी साथ में एक और महत्वपूर्ण विभाग-योजना विभाग के मन्त्री हैं। स्पष्ट है कि वे श्रम विभाग की ओर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे।

सरकार की श्रमनीति कैसी है—इसका परीक्षण बोनस के मसले से की जा सकती है। सरकार ने यथा स्थितिवादी अध्यादेश जारी कर उसे अधिनियम में बदल कर मजदूरों की आशाओं पर तुषारापात किया है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार बोनस की अदायगी में टालमटोल कर रही है।

मूल्य सूचकांक के निर्धारण की पद्धति में सुधार हेतु एक बार संकेत देने के बावजूद सरकार ने सुधार सम्बन्धी 'रथ कमेटी' की सिफारिशें अस्वीकार कर दी हैं। मजदूरों को पूर्णतया सन्तुष्ट न होने पर भी उन सिफारिशों में वर्तमान पद्धति से अच्छे सुझाव थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा अस्वीकृति का एकमेव कारण यह है कि इस कमेटी का गठन पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। यह बात सरकार के उद्देश्यों को ही संशयास्पद बना देती है।

एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक बनाने के लिये अभी कुछ भी नहीं किया गया। भूतपूर्व श्रममन्त्री श्री रवीन्द्र वर्मा इसके लिये निरन्तर प्रयत्नशील थे और मजदूर संघों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, चाहे उसका प्रतिफल संतोषजनक न रहा हो, किन्तु अब तो किसी भी प्रयास की प्रक्रिया ही बन्द हो गयी है।

मजदूरों के साथ नियतकालिक विचार विमर्श तो मानों अनावश्यक ही कर दिया गया है। प्रधान मन्त्री एवं श्रम मन्त्री श्री टी० अन्जैय्या के साथ बातचीत के

उपरान्त कुछ अपेक्षा एवं आशा जगी थी, पर वह समाप्त हो गयी है। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हेतु एक बार केवल निमन्त्रण मिला था, किन्तु अभी तक उसे सम्पन्न करने हेतु कुछ भी नहीं किया गया।

विभिन्न श्रम संगठनों की सापेक्ष शक्ति ज्ञात करने सम्बन्धी नीति अभी स्पष्ट नहीं है। यह प्रतीत होता है कि अपने को पूरी तरह सलाहकार के सामने समर्पित कर आई० एन० टी० यू० सी० की पीठ ठोंकते रहने के सिवाय श्रम मन्त्री के लिये कोई दूसरा चारा नहीं है।

इस सरकार के आने के पूर्व यह तय हुआ था कि आई० यन० टी० यू० सी०, भा० म० संघ, ए० आई० टी० यू० सी०, हिन्द मजदूर सभा तथा सी० आई० टी० यू०—ये ५ मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े संगठन हैं। इस बात को सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामने भी स्वीकार किया है और इन सभी श्रम सगठनों के प्रतिनिधियों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिलित होने के लिये आमन्त्रित कर आई० एन० टी० यू०सी० का एकाधिकार समाप्त किया था, किन्तु वर्तमान सरकार ने पुनः कदम पीछे खींच-कर आई० एल० ओ० के ६६वें अधिवेशन में केवल आई० एन० टी० यू० सी० को भेजा और घड़ी की सुई उल्टा घुमा दिया।

ट्रेड यूनियनों की एकता एवं संयुक्त मोर्चे

१९७८ के जयपुर अधिवेशन में हमने यह स्पष्ट किया था कि कुछ समान विचारों वाले श्रम संगठनों के एक हो जाने का प्रयास निष्फल हो गया है। उस समय हमने यह सुझाव रखा था कि एकता के लिये प्रथम चरण में ऐसे सभी श्रम संगठनों का एक महासंघ (कान्फेडरेशन) बनाया जाय, किन्तु इस सम्बन्ध में अन्य संगठनों की ओर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला।

जून १९७८ में आये राजनीतिक परिवर्तन के कारण कुछ मजदूर संगठनों के रुख में परिवर्तन आया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि उन संगठनों के उद्देश्य मूलतः राजनीतिक हैं, तथा सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ उनके विचार भी बदलते रहते हैं।

सन् १९७९ में बोनस पर हुये आन्दोलन में उन मजदूर संघों के राजनैतिक झुकावों को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। भारतीय मजदूर संघ का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि राजनैतिक परिवर्तन अथवा सत्ताधिष्ठित दल को सामने रखकर ट्रेड यूनियनें निर्णय लेने लगेंगी तो निश्चित ही मजदूर हितों की बलि चढ़ती रहेगी। विगत २ वर्षों की घटनाओं से रेल कर्मचारियों ने इसका कटु अनुभव किया है।

राष्ट्रहित को सामने रखते हुये मजदूरों का हित भारतीय मजदूर संघ का सदैव से लक्ष रहा है। वह इस बात की चिन्ता नहीं करता कि किस समय कौन सा दल राज्य कर रहा है। जयपुर अधिवेशन में निर्धारित किसी भी निर्वाचित सरकार के साथ 'प्रत्युत्तरीय सहयोग' की नीति पर ही भारतीय मजदूर संघ चल रहा है। यह सन्तोष का विषय है कि आम मजदूरों ने इस नीति का स्वागत किया है।

मजदूर हितों के लिये समान स्तर पर रहकर संयुक्त मोर्चा बनाने में भारतीय मजदूर संघ कभी पीछे नहीं रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अन्य मजदूर समस्याओं के साथ विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर आयोजित हैदराबाद, दिल्ली एवं बंगलौर के सम्मेलनों में

भारतीय मजदूर संघ ने पूरा सहयोग दिया। इन कर्मचारियों के लिये बंगलौर व अन्य स्थानों पर हुये आंदोलनों में भारतीय मजदूर संघ का सहयोग स्पष्ट है।

१९७८ में औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का विरोध करने में हम अन्य श्रम संगठनों के साथ रहे।

रेलों पर संघर्ष में हम अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर खड़े हुये तथा अन्य जहां हिचकिचा रहे थे, हमने ही अगुवाई करके मार्ग निकाला।

बीमा निगम कर्मचारियों के हमारे महासंघ--यन० ओ० आई० डब्लू० ने न केवल अन्य संगठनों के साथ संघर्षशील रहा, अपितु कई मामलों में स्वयं आगे बढ़ता रहा।

बैंकिंग क्षेत्र में राजनैतिक उद्देश्यों से वशीभूत होकर ए० आई० बी० ई० ए० और इम्बेक जब संघर्ष उभारना चाहते थे, तब हमारे महासंघ यन० ओ० बी० डब्लू० ने उसका विरोध किया, किन्तु जब कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत का दौर चला तो हमने एक सतर्क पहरेदार की तरह मजदूर हितों को ध्यान में रखा और निगरानी रखकर उसका अतिक्रमण नहीं होने दिया तथा सफलता प्राप्त की।

पश्चिम बंगाल में अन्य समान विचार वाले संगठनों के सहयोग से भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर हितों को बलि नहीं चढ़ने दी। अपने ही रक्त मांस के वहां के मजदूर भले ही कुछ दिनों से कुछ मात्रा में विदेशी विचार और विदेश प्यार के प्रभाव में हैं किन्तु अपने संगठन ने यह दायित्व लिया है कि उनकी समस्याओं का हल करते हुये उन्हें भी देश की मूलधारा के साथ जोड़कर ही दम लेंगे।

ऐसी अनेक घटनायें उल्लेख की जा सकती हैं। इन सबसे यह स्पष्ट है कि मजदूर हित के लिये हम सदैव सभी के साथ सहयोग करते हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी न किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध होकर चलने वाली अन्य यूनियनें अपने राजनैतिक मालिकों की सुविधा के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती हैं।

इसी कारण से कुछ स्थानों पर भारतीय मजदूर संघ को अलग-अलग रखने का भी प्रयास रहा है। बंगलौर में तथा कथित मान्यता प्राप्त व वार्ता में प्रतिनिधित्व प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिवनों ने भारतीय मजदूर संघ को कमजोर करने

व समाप्त करने की दृष्टि से उसको अलग रखा किन्तु बी० ई० एल० की हमारी यूनियन ने बी० एच० ई० एल० के बराबर वेतन का अकेले ही मसला उठाया और उस आन्दोलन को मजदूरों का इतना समर्थन मिला कि अन्यों को हमारे साथ आना पड़ा और उन्होंने अपनी भूल भी स्वीकार की।

इन सभी परिस्थितियों से गुजरते हुये भारतीय मजदूर संघ सशक्त होकर सामने आया है। यदि दूसरे चाहें तो हम तत्परता से सहयोग देते हैं, यदि वे इच्छुक न हों तो हम स्वयं ही अकेले आगे बढ़ते हैं और यदि वे विरोध करें तो उनके विरोध के बावजूद कदम बढ़ाते रहते हैं। हमारे कदम कभी रुके नहीं—भविष्य में भी हम आगे बढ़ते ही रहेंगे।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन में हिंसा

इन दिनों मजदूर आन्दोलन के क्रिया-कलापों में हिन्सा तथा गुण्डागर्दी में वृद्धि हुई है। भारतीय मजदूर संघ इसकी घोर निन्दा करता है किन्तु यह भी मानता है कि प्रत्येक हिंसक कार्यवाही के लिये मजदूरों को ही जिम्मेवार बताना गलत है। हिन्सक कार्यवाहियों में प्रबन्धक वर्ग का कितना हाथ है, इसकी भी जांच होनी चाहिये। साथ ही इसकी रोक के लिये सरकार, प्रबन्धक व मजदूर—तीनों को सम्मिलित करके विचार करना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ के कार्य की प्रगति

अपने पंचम अखिल भारतीय अधिवेशन में दि० २१ से २३ अप्रैल ७८ को जयपुर में हम लोग मिले थे। उस समय वर्ष १९७७ के अन्त तक १०,८३,४८८ सदस्य संख्या तथा १५५५ ट्रेड यूनियनें भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध थीं। इस समय यह संख्या (वर्ष ८० तक) बढ़कर १७७६ ट्रेड यूनियनें एवं १८०५९१० सदस्यता तक पहुँच चुकी है।

प्रदेशवार विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया है।

अपने कार्य को स्थापित हुये आज २५ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हम लोगों ने रजत जयन्ती बर्ष के पूरा होने के एक वर्ष बाद तक के लिये एक लक्ष रखा है कि २३ जुलाई ८१ तक २५०० यूनियनें तथा २५ लाख सदस्य संख्या भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध हो जावें। उस दृष्टि से जहां आशातीत सफलता मिली है, वहीं अभी उस लक्ष्य तक पहुँचने में थोड़ी कमी भी रह गयी है। वहां तक हमें देर सवेर पहुँचना है।

इस अवधि में नागालैण्ड में ट्रान्सपोर्ट मजदूरों की तथा त्रिपुरा में चाय मजदूरों की एक-एक प्रभावी यूनियनों ने भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्धता लिया है। इस प्रकार उन नये तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में भी अपने कार्य का श्रीगणेश हुआ है। इस वर्ष की यह एक बड़ी उपलब्धि है।

केन्द्रीय औद्योगिक महासंघों के कार्यों में प्रगति व उपलब्धियों का यहाँ थोड़े में दिग्दर्शन किया जा रहा है--

भारतीय खदान मजदूर संघ

संघ की इस बीच उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश में इसकी इकाइयां फैल चुकी हैं। खदान से सम्बन्धित अखिल भारतीय स्तर की सभी समितियों में इसे

प्रतिनिधित्व मिला है। अभी इस वर्ष उखड़ा (बंगाल) में सम्पन्न हुये अखिल भारतीय अधिवेशन में ११०० से भी ऊपर की संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अ० भा० इस्पात मजदूर संघ

संघ का कार्य देश के सभी ८ कारखानों में है। बोकारो में अनपेक्षित कार्य की वृद्धि हुयी है। बहुत संघर्ष करने के पश्चात् बर्नपुर की यूनियन ने अन्य यूनियनों के समान न केवल मान्यता प्राप्त की है वरन् कुछ यूनियनों से बहुत आगे की सदस्यता करके मजदूरों का प्रभावी समर्थन भी प्राप्त किया है।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

संघ को यद्यपि पक्षपात व भेदभाव के कारण अभी भी अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, तो भी उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर पंजाब, बंगाल, मध्यप्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तामिलनाडु तथा केरल में सम्बन्धित यूनियनें कार्य कर रही हैं। इनमें १२ यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं। जबलपुर में सम्पन्न हुये इस वर्ष के ५वें अखिल भारतीय अधिवेशन में ७०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शाहजहांपुर में बहुत लम्बे अरसे के पश्चात २४ मजदूरों का निलम्बन समाप्त कराने में भा० प्रतिरक्षा मजदूर संघ को सफलता मिली है। ४३ दिन की भूख हड़ताल के पश्चात अम्बरनाथ की यूनियन के महामन्त्री का निष्कासन समाप्त कराने के लिए बाध्य किया गया। पठानकोट, जालन्धर व आगरा के अपने कार्यकर्ताओं के अकारण स्थानान्तरण को आन्दोलन करके समाप्त कराया गया।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेन्स वर्कर्स

वर्कर्स का कार्य द्रुतिगति से बढ़ा है। अब तक ४४ मंडलों में से ३५ मंडल में अपनी रजिस्टर्ड यूनियनें सक्रिय हैं। इसे वर्ष १९७३ से मजदूर समस्याओं पर वार्ता आदि करने हेतु प्रतिनिधित्व मिला है।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ जनरल इन्स्योरेन्स वर्कर्स

वर्कर्स की इस वर्ष कानपुर, दिल्ली तथा हुबली (कर्नाटक) की ३ यूनियनों

ने सम्मिलित आकर स्थापना की है। जनरल इन्स्योरेन्स के मजदूरों के लिए इस राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

अ० भारतीय सीमेन्ट मजदूर संघ

संघ का कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा कर्नाटक में भलीभाँति फैला है। इसे सीमेन्ट वेतन मण्डल में प्रतिनिधित्व मिला है।

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ

महासंघ का कार्य क्रमशः बढ़कर हिमाँचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार बंगाल, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश तक पहुंचा है। पथ परिवहन उद्योग में पहली ही बार इस महासंघ ने संसद भवन बोट क्लब पर दि० ३ अक्टूबर ८० को १५५० से भी ऊपर परिवहन कर्मचारियों द्वारा पूरे दिन का धरना देकर समूचे देश के लिये एक सेवा नियमावली, वेतन क्रम एवं समस्त सुविधायें समान करने की मांग की है।

अ० भारतीय विद्युत मजदूर संघ

संघ का कार्य १२ राज्यों तक फैला हुआ है। बहुतांश राज्यों में इसे मान्यता मिली है। बम्बई उच्च न्यायालय से अपने इस महासंघ ने ऐतिहासिक विवाद जीतकर विद्युत उद्योग के मजदूर बोनस अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं—कराया है। मध्य प्रदेश में अपनी यूनियन के प्रयास से १ रुपये ३० पैसे प्रति मूल्य सूचकांक की दर के स्थान पर १ रुपये ४० पैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश में विद्युत मजदूरों की हड़ताल के समय अपनी यूनियन ने महत्वपूर्ण भाग लिया था तथा अनेक मांगों को लेकर ५ हजार से भी ऊपर को संख्या में शक्तिभवन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान में अपने ही प्रयास से २२ हजार कैजुअल मजदूरों को नियमित कराया गया।

अ० भा० सुगर मिल मजदूर संघ

संघ एक शक्तिशाली महासंघ है। तृतीय बेज बोर्ड की मांग को लेकर

हजारों कर्मचारियों ने श्रम शक्ति भवन दिल्ली पर धरना दिया। इसका कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों तक फैला हुआ है। डोईवाला (देहरादून) सुगर मिल के मजदूरों को बड़े संघर्ष करके पर्वतीय भत्ता दिलाने में सफलता पायी है। साथा, रोहाना, शामली तथा देवबन्द (उत्तर प्रदेश) के मजदूरों को क्षतिग्रस्त मुआवजे का १ लाख से अधिक रुपये दिलाया है।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

संघ ने ८ मई १९७९ के दिन संसद भवन पर १० हजार से भी ऊपर कर्मचारियों का प्रदर्शन आयोजित करके अपनी शक्ति का परिचय दिया है। दि० २७ व २८ अक्टूबर ८० को लखनऊ में सम्पन्न हुये ६ठें अखिल भारतीय अधिवेशन में कुल २२०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। १० नवम्बर ७९ की दिल्ली में आयोजित रेल की समस्त यूनियनों की संयुक्त बैठक में अकेले भारतीय रेल मजदूर संघ ने 'बोनस' देने की मांग पर २० दिसम्बर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की। इस समय भी अपनी ही यूनियनें उत्पादकता बोनस के स्थान पर विलम्बित वेतन के रूप में वार्षिक बोनस की माँग लेकर आन्दोलन कर रही हैं। २३ दिसम्बर ८० को समूचे देश में हजारों स्थान पर वार्षिक बोनस सहित अपने १० सूत्री मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन व सभायें की गयी हैं। मध्य रेलवे में स्कूल चपरासी, सफाई वाले तथा जल वितरण संस्थानों में महिलाओं की नियुक्ति कराने हेतु सफल आन्दोलन किया गया है।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स

वर्कर्स द्वारा बैंकिंग उद्योग की लगभग सभी शाखाओं की अनेक नई इकाइयों में प्रवेश हुआ है। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की मांगों के विवाद में सीटू समर्थित प्रमुख यूनियन के विरोध के बावजूद भी अन्तरिम राहत प्राप्त करने में अपने को अच्छी सफलता मिली। सीटू समर्थित यूनियन के समझौते के प्रश्न पर मत संग्रह में अपने पक्ष में लगभग ४१ प्रतिशत आये कर्मचारियों की संख्या से सभी को आशा एवं उत्साह मिला है। यद्यपि ए. आई. आर. बी. इ. ए. को छोड़कर अन्य सभी यूनियनें अपने साथ थीं, तो भी प्रमुख भूमिका अपनी यूनियन ने ही अदा की। कानपुर, पटना, नागपुर व मद्रास आदि स्थानों पर सर्वाधिक मत प्राप्त

कर पूर्व से चली आयी हुई प्रमुख यूनियन के वर्चस्व को चुनौती दी गयी। ट्रिब्यूनल सम्बन्धी उक्त विवाद में अपने अ० भा० कोषाध्यक्ष श्री मनहर भाई का योगदान विशेष उल्लेखनीय है।

ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों में तेजी से कार्य की प्रगति हुई है। स्टेट बैंक में भी अपने कार्य की द्रुतगति से विस्तार हुआ है। विगत ५ व ६ अक्टूबर ७९ को नागपुर में स्टेट बैंक की अपनी यूनियन का ऐतिहासिक अखिल भारतीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ है, जिसमें लगभग १५०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इण्डियन बैंक एसोशियन से एन० ओ० बी० डब्लू० की अनेक बार वार्ता हुयी। जब वार्ता असफल हुयी तो दिसम्बर ७८ में २ दिन की हड़ताल रखी गयी थी। पुनः द्विपक्षीय वार्ता में समझौता हुआ और कर्मचारियों की मांगों को बहुत अंशों तक पूरा कराया गया।

अभी उक्त महासंघ का १ से ३ नवम्बर ८० को पूना में अखिल भारतीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ है, जिसमें २१०० से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स

आफिसर्स का कार्य लगभग सभी बैंकों में प्रारम्भ हो चुका है। इसने बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योग में राष्ट्रीय विचार धारा रखने वाले आफिसरों के एक केन्द्र की आवश्यकता की पूर्ति की है। अभी १० से १२ दिसम्बर ८० को बम्बई में इसकी ओर से एक शिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ था, जिसमें ११० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ

जयपुर अधिवेशन के पश्चात यह एक नया केन्द्रीय औद्योगिक महासंघ स्थापित हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस महासंघ को वेतन पुनरीक्षण के अवसर पर आब्जर्वर के नाते भी प्रतिनिधित्व मिला है। इसकी क्रमशः प्रगति हो रही है।

अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर संघ

संघ की १० राज्यों में यूनियनें सक्रिय रूप से चल रही हैं। इस एक वर्ष में

इसकी ओर से छोटे बड़े कुल ६१ सम्मेलन हुये हैं, जिसमें मजदूरों की समस्याओं पर विचार किया गया।

भारतीय डाक तार कर्मचारी महासंघ

महासंघ ने अल्प समय में सभी राज्यों में तथा कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में अपने प्रभावी कार्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस महासंघ के साथ ही सम्बद्ध १० यूनियनों को भी मान्यता प्राप्त है।

भारतीय जूट मजदूर संघ

संघ का कार्य प्रभावी रूप ग्रहण कर चुका है। पूर्व से चल रहीं अनेक यूनियनों को पीछे ढकेल कर इसने मजदूरों का समर्थन प्राप्त किया है।

सहयोगी महासंघ

अपने विचारों एवं सहयोग से चलने वाले सरकारी कर्मचारियों के दो अखिल भारतीय श्रम संगठनों की सदस्यता भी इस अवधि में पर्याप्त बढ़ी है। अभी हाल ही में गवर्नमेन्ट इम्पलाइज नेशनल कान्फीडरेशन (राज्य व केन्द्र) का द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन दिल्ली में सम्पन्न हुआ है, जिसमें देश के अधिकांश राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा है।

परिशिष्ट क्र० २ में अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघों की सम्बद्ध यूनियनों की संख्या व सदस्यता अंकित है।

संघर्ष, समझौते तथा उपलब्धियां आदि

महत्वपूर्ण उद्योगों व बड़े कारखानों के कार्यकलाप सुगमता से लोगों के ध्यान में आ जाते हैं, किन्तु छोटे-छोटे कारखानों व उद्योगों तथा खेतिहर मजदूरों व बुनकरों के बीच ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों की कम लोगों को ही जानकारी हो पाती है। यहां हम अधिकांश ऐसे ही उपेक्षित संस्थानों व कारखानों के अन्तर्गत काम करने वाली अपनी ट्रेड यूनियनों की उल्लेखनीय गतिविधियों का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहे हैं।

राजस्थान

कोटा के श्रीराम रेयन्स कर्मचारी संघ ने ८६ दिन की तालाबन्दी के विरुद्ध संघर्ष कर सरकार एवं ट्रिब्युनल के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेन्ज किया तथा १३ दिन की हड़ताल करके अपने मांग पत्र पर समझौता कराया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने अभी थोड़े दिन पहले १५०० सेवामुक्त किये गये कर्मचारियों को पुनः काम पर लगवाया। टोंक जिले में बीड़ी, कारपेट, सिंचाई, चमड़ा, बिजली आदि में लम्बे संघर्षों के द्वारा न्यूनतम वेतन व साप्ताहिक अवकाश लागू कराया। ४०० बीड़ी तथा २०० सिंचाई विभाग के निकाले गये मजदूरों को पुनः काम पर वापस रखवाया। मजदूरों को सूती व ऊनी वर्दी, रेगुलर ग्रेड, उपार्जित अवकाश, न्यूनतम वेतन भुगतान आदि का लगभग ४.१५ लाख रुपया दिलवाया। हिन्दुस्तान कापर के खेतड़ी कापर मजदूर संघ ने दसवर्षीय प्रमोशन योजना, भर्ती नियमों में संशोधन आश्रितों को नौकरी, शिक्षा व चिकित्सा सुविधा आदि दिलाये हैं। जयपुर मेटल में १०० रुपये मासिक वेतन वृद्धि करवाई। माडर्न सिन्टेक्स मे ३० रुपये, जेनसन में २० रुपये, नागर कैमिकल्स में ९ रुपये मासिक वेतन वृद्धि कराने में सफलता मिली। अलवर के सुनील सिनेकेम में २० प्रतिशत इक्सग्रेसिया, सहकारी मिल गुलाबपुरा में २० प्रतिशत बोनस तथा राजस्थान स्पिनिंग मिल भीलवाड़ा में १७.५० प्रतिशत बोनस दिलाया गया।

हरियाणा

नगरपालिकाओं पर धरना व प्रदर्शन करके मांगों को हासिल किया गया है। माचिस उद्योग में न्यूनतम वेतन लागू कराने में यूनियन सफल हुयी है।

दिल्ली

कभी यूनियनों के संयुक्त मोर्चे के द्वारा १४ मास की लम्बी हड़ताल करके कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को ४५ रुपये की वेतन बढ़ोत्तरी दिलवायी गयी है। डी. डी. ए स्लम में एक महीने आन्दोलन चलाकर २७ में से २५ मांगें पूरी करायी गयीं। जलसंस्थान की बहुचर्चित अभूतपूर्व हड़ताल के फलस्वरूप कर्मचारियों की अनेक मांगें पूरी करायी गयीं। नोवेक्श ड्राई क्लीनर्स में २८ दिन की हड़ताल के पश्चात् १३ कर्मचारियों को काम पर रखाया गया।

पंजाब

मालवा सुगर मिल घुरी में आन्दोलन चलाकर बोनस के अतिरिक्त १ लाख ५ हजार इक्सग्रेसिया दिलाया गया। कुराली नगर पालिका में हड़ताल के फलस्वरूप बकाये पैसे का भुगतान कराने हेतु बाध्य किया गया। इण्डिया रबर इन्डस्ट्रीज जालन्धर में २५ रुपये मासिक वेतन वृद्धि तथा १४ प्रतिशत बोनस, कपूर सिल्क एण्ड विविंग मिल्स अमृतसर में १२ रुपये मंहगाई भत्ता वृद्धि तथा ब्रेवरीज लि० लुधियाना में आन्दोलन करके मांगों को प्राप्त किया गया।

वेस्टर्न कमाण्ड एम. ई. एस. में ५४ दिन की क्रमिक भूख हड़ताल एवं अनेक संघर्ष के बाद राशन देने की मांग मनवाई गयी। पंजाब नगरपालिका कर्मचारी महासंघ द्वारा अनेक संघर्ष के उपरान्त वेतन का पुनरीक्षण कराया गया। नगर निगम लुधियाना में भूख हड़ताल करके ३ वर्ष से ऊपर सेवारत कर्मचारियों को रेगुलर तथा ५ वर्षों से ऊपर वाले को स्थायी कराया गया।

जम्मू कश्मीर

जम्मू व कश्मीर के जम्मू फ्लोर मिल में २५ रुपये से ६५ रुपये, पी. डब्लू डी. में ३० रुपये, सुपर बाजार में १० रुपये से २० रुपये तक मासिक

वेतन वृद्धि करायी गयी। चिनाव टेक्सटाइल मिल्स कटुआ में १० प्रतिशत बोनस तथा १५ रुपये से १८ रुपये तक मासिक वेतन वृद्धि, एन० सी० सी० यूनियन सलाल में अधिक दिनों तक आन्दोलन करके मेडिकल एलाउन्स, छुट्टियाँ, ट्रान्सपोर्ट, क्वार्टर आदि की सुविधायें दिलाने में सफलता मिली।

चण्डीगढ़

प्रायः सभी कारखानों में भारतीय मजदूर संघ ने वेतन वृद्धि कराने में सफलता पायी है।

हिमांचल प्रदेश

सार्वजनिक निर्माण विभाग कर्मचारियों को आन्दोलन व हड़ताल के माध्यम से मांगों की पूर्ति कराने में भारतीय मजदूर संघ अग्रसर रहा है।

महाराष्ट्र

जनता सरकारी बैंक, थाना के कर्मचारियों का १०० रुपये वेतन की बढ़ोत्तरी करायी गयी। डोम्बिवली नगरपालिका के कर्मचारियों को प्रतिदिन ३ रुपये व ४ रुपये की मजदूरी बढ़वाई गयी। विद्युत विभाग के नासिक के ५१ कर्मचारियों ने ११० किलोमीटर का पैदल मार्च, घेराव तथा ६ दिन की भूख हड़ताल एवं १३ मजदूरों को जेल में रहने के उपरान्त ८० आदमियों को नियमित कराया गया, झालरी भत्ते में २५ रुपये से बढ़ाकर ११० रुपये कराया गया तथा चिकित्सा सुविधा में दूनी बढ़ोत्तरी करायी गयी।

घाडगे पाटिल ट्रान्सपोर्ट कोल्हापुर में ५२ दिन हड़ताल में ७८ मजदूरों पर फौजदारी के मुकदमे कायम थे—सभी को निर्दोष मुक्त कराने में सफलता मिली। परिवहन में पक्षपात पूर्ण रवैये के विरुद्ध कोल्हापुर के वर्कशाप में दो दिन की हड़ताल के फलस्वरूप प्रबन्धकों को समझौता करके हमारी मांगों को मानना पड़ा। इतना ही नहीं ७०० मजदूरों का विशाल प्रदर्शन भी निकला और १३०० कर्मचारी अपने महाराष्ट्र मोटर कामगार संघ के सदस्य बने। मेडले फार्मास्युटिकल कम्पनी औरंगाबाद में मालिकानों ने साम्प्रदायिकता फैलाने के भरसक प्रयास किया, क्योंकि वे स्वयं जहां मुसलमान थे, वहीं कर्मचारी भी ९० प्रतिशत मुसलमान

ही हैं। किन्तु तालाबन्दी व अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न करने के बाद भी कोई कर्मचारी उनके बहकावे में नहीं आया और बुरकाधारी महिलायें कन्धे पर भगवा झण्डा धारण करके भारत माता की जय के नारे के साथ प्रदर्शन करती रहीं। ३ महीने के पश्चात् यूनियन को विजय मिली है। लाइम केमिकल्स रोहा में ७ दिन की हड़ताल के पश्चात् ११० रुपये से १३० रुपये प्रतिमास की वेतन वृद्धि कराने में यूनियन को सफलता मिली है। गीता बिल्डिंग गाय देवी मुम्बई सोसायटी के ५५ घरेलू मजदूरों के प्रदर्शन के उपरान्त २५ रुपये से ४० रुपये तक मासिक मजदूरी बढ़वायी गयी। घरेलू कामगारों ने लगभग ५०० की संख्या में विधान सभा पर धरना दिया तथा मुख्यमन्त्री को ज्ञापन देकर विधेयक लाने का आश्वासन प्राप्त किया।

घंतक अणि कम्पनी ट्यूबवेल इन्जीनियरिंग अक्सेल इन्डस्ट्रीज, एम० जे० पटेल, फिल्म सेंटर, सरदार इन्जीनियरिंग, बाम्बे फिल्म लेबोरेटरीज, नवरंग सिने सेन्टर्स, लकावी, मारिस, मुंगी, महाराष्ट्र पाकेजिंग, दत्तात्रय इन्जीनियरिंग आदि संस्थानों में अच्छे समझौते करके २० प्रतिशत तक बोनस दिलाने में सफलता मिली है।

ज्योस्ट इन्जीनियरिंग में ७५ रुपये से १३० रुपये की तथा प्लास्टिक कोर कारपोरेशन में ७० रुपये से १४० रुपये की प्रतिमास वेतन वृद्धि करायी गयी।

६ खदानों के कामगार डा० दत्ता सामंत की गुण्डागर्दी के बावजूद उन्हें छोड़कर अपने साथ आये। फलस्वरूप उन्हें महंगाई भत्ता एवं २० प्रतिशत बोनस दिलवाने में सफलता मिली।

बेंगुर्ला राजापुर व खेड चिपलूण सतारा के नगर परिषद कर्मचारियों को भोले आयोग का लाभ दिलाया गया।

ओखाड़ फार्मास्युटिकल्स औरंगाबाद में ७५ रुपये से १५० रुपये तक वेतन वृद्धि एवं १८ प्रतिशत बोनस, सिल्हट, लाइट, औरंगाबाद में १५० रुपये से १७५ रुपये तक, इण्डियन ह्यूप पाइप कम्पनी औरंगाबाद में ७५ रुपये से १५० रुपये तक की वेतन वृद्धि, जे० जे० ग्लास इन्डस्ट्रीज पूणे में ११५ रुपये की वेतन वृद्धि तथा १८ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक बोनस, सह्याद्रि में १२५ से १७५ रुपये तक,

लुमार में ६० रुपये से ६५ रुपये तक, इण्डियन इलैक्ट्रानिक मुम्बई में १४० रुपये, एल० आर० ट्रेडर्स मुम्बई में १३५ रु०, निर्मल कन्डेन्सर्स में ६० रुपये वेतन वृद्धि तथा माडर्नसिन्सटीन में १६.५० प्रतिशत एवं बनतक मुम्बई में २० प्रतिशत बोनस दिलवाने में यूनियनों को सफलता मिली है।

गुजरात

पोरबन्दर स्थित सौराष्ट्र केमिकल्स में अपना कार्य प्रभावी हुआ है तथा २ हजार से भी ऊपर मजदूर अपनी यूनियन के सदस्य बने हैं। अहमदाबाद के निगम एवं डेरी में २ वर्षों से निलम्बित कर्मचारियों को आन्दोलन करके काम पर वापस रखाया गया।

मध्यप्रदेश

कपड़ा मिलों में आन्दोलन करके सकलेचा एवार्ड लागू कराया गया। बीड़ी, सिंचाई एवं पी. डब्लू. डी में न्यूनतम प्रतिदिन की मजदूरी ६ रुपये निर्धारित करायी गयी। परिवहन में एक मास तक की हड़ताल व आन्दोलन करके अनेक मांगों की पूर्ति करायी गयी। वस्त्र उद्योग तथा लोक निर्माण आदि उद्योगों में कार्यरत ठेकेदार श्रमिकों के शोषण की समाप्ति के लिए अनेक आन्दोलन करके शासन से एक समिति के निर्माण की घोषणा करवाई गयी तथा उन्हें अनेक राहत दिलवाई गयी।

विदर्भ

अमरावती नगर परिषद कर्मचारी संघ द्वारा १५ दिनों का धरना देकर ३७५ मजदूरों को स्थायी कराया गया। जनता मिल मजदूर संघ पुलगांव ने आंदोलन करके २० प्रतिशत बोनस प्राप्त किया। हड़ताल करके बुलढ़ाना के पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के फार्म मजदूरों की वरिष्ठता सूची तैय्यार करायी गयी, साप्ताहिक छुट्टी तथा बकाए वेतन का भुगतान कराया गया।

नागपुर तहसील के बुनकर मजदूरों के डेली वेजेज में बढ़ोत्तरी करायी गयी। अकोला के सहकारी बैंक कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी करायी गयी।

कानपुर स्थित जे० के० काटन मिल में १६ प्रतिशत तथा जे० के० जूट मिल में ४७.५० रुपये की वेतन वृद्धि करायी गयी। म्योर मिल में ५ कर्मचारियों के विवाद में समझौता करके उन्हें १ लाख ५० हजार रुपए दिलवाया गया। लाल इमली ऊलेन में आन्दोलन के द्वारा बाथ एण्ड वार्ड कर्मचारियों के अवकाश सुविधा में वृद्धि करायी गयी तथा उन्हें एरियर का २१ हजार रुपए दिलवाया गया। विक्टोरिया मिल में अधिग्रहण से पूर्व का १२ लाख रुपए मजदूरों का भुगतान कराया गया।

६ जून, १९७९ के दिन भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर चुपके से मालिकों ने श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में अन्य सभी श्रम संगठनों के साथ समझौता करके जनवरी से मार्च तक का एरियर ५४ लाख रुपया छोड़ दिया था, उसके विरोध में अकेले भारतीय मजदूर संघ ने २० अगस्त को सूती मिलों के ४० हजार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कराकर इस भ्रष्टाचार का सफल प्रतिकार किया। कानपुर के विद्युत पावर हाऊस के १४ कर्मचारियों के ओवर टाइम का २२ हजार बकाये का भुगतान कराया गया। उत्तर रेलवे कानपुर में आन्दोलन करके १३४ कर्मचारियों की छटनी रोकी गयी। बैठकी के विरुद्ध घेराव में ३४ रेल कर्मचारियों ने जेल की सजा भी काटी है। जयपुरिया स्कूल में सेवारत गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन में २५ रुपए की तुरन्त वृद्धि तथा अप्रैल से प्रति कर्मचारी के वेतन में करीब १०० रुपए मासिक की वृद्धि करायी गयी। जे० के० काटन मिल तथा एलगिन मिल नं० २ में कार्य के समय दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को ३६ हजार तथा एक हजार रुपया मृतक क्रिया निमित्त दिलवाया गया।

वाराणसी स्थित साहू केमिकल्स में मुकदमे में जीतकर मजदूरों को ६ लाख रुपए दिलवाया गया। अजीतमल कारखाने में ८.३३ प्रतिशत के स्थान पर ११.३३ प्रतिशत बोनस वितरित कराया गया। स्पिनिंग मिल भदोही के कर्मचारियों को संघर्ष के द्वारा वेतन में ५० रुपए मासिक की वृद्धि मिली।

ओबरा में १२६ विद्युत मजदूरों की बहाली, कनहर परियोजना के १४ मजदूरों को आन्दोलन के माध्यम से काम पर वापसी, अल्युमिनियम कर्मचारियों के वेतन में ३५ रुपये से ६० रुपये तक वेतन वृद्धि तथा ३०० रुपए प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी यात्रा भत्ता दिलवाने में सफलता मिली।

मथुरा के त्रिवेणी इन्जीनियरिंग में ४१ दिन हड़ताल करके निष्कासित कर्मचारियों को काम पर पैसे सहित वापस आने में सफलता मिली तथा ४ कर्मचारियों को मुआवजे में १ लाख १० हजार रुपये दिलवाया गया।

अलीगढ़ के गान्धी नेत्र चिकित्सालय कर्मचारियों के वेतन में २५६ रुपये की वृद्धि करायी गयी। टाइगर हार्ड बेयर एण्ड टूल्स लि० के कर्मचारियों को १० रुपये अन्तरिम सहायता तथा ८ रुपये वेतन वृद्धि कराया गया। चेन फैक्ट्री में १० रुपये वेतन वृद्धि १५ प्रतिशत बोनस वितरित कराया गया।

बुलन्दशहर के कोआपरेटिव टेक्सटाइल मिल में १४५ कर्मचारियों की छँटनी रुकवाई गयी। गाजियाबाद क्रेन-फैक्ट्री में संघर्ष करके ५० रुपये से ६७ रुपये तक की वेतन वृद्धि करायी गयी।

बी० एच० ई० एल० हरिद्वार में संयुक्त मोर्चे के माध्यम से ४४४ रुपये के स्थान पर ४८८ रुपये वेतन कराया गया। कैजुअल व टेम्परेरी के वेतन में १२.५० प्रतिशत की वृद्धि करायी गयी। एन्सीलयरी कर्मचारियों के ४ इकाइयों में बोनस लागू कराया गया। सभी कर्मचारियों को वर्दी दिलायी गयी।

देहरादून कोआपरेटिव टेक्सटाइल मिल में मूल वेतन मे ७० पैसे प्रतिदिन तथा डेरी कर्मचारियों के वेतन में ३० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करायी गयी।

पथर चट्टा नैनीताल के खेतिहर मजदूरों के निरन्तर संघर्ष द्वारा वेतन में वृद्धि तथा सेवा शर्तों में सुधार कराया गया।

बिहार

अपनी यूनियन के पहल करने पर ही हैवी इन्जीनियरिंग राँची में वेतन में ७३ रुपये की मासिक वृद्धि हुयी। उत्तरी कर्णपुर एवं धनवाद कोइलरी में क्रमशः ४०० एवं ८०० कैजुअल मजदूरों को पुनः काम दिलवाया गया। जमशेदपुर टाटा-नगर में १० हजार ठेके के मजदूरों को रेगुलर कराया गया। टेल्को में ३०० कैजुअलों को रेगुलर कराने में सफलता मिली। कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय धनवाद में हड़ताल, प्रदर्शन, धरना, राज्य श्रम मन्त्री के निवास स्थान दिल्ली में धरना आदि आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों के अवलम्बन से कार्यमुक्ति,

निलम्बन तथा स्थानान्तरण आदि में विजय प्राप्त कर पूर्व स्थिति लाने में सफलता मिली। टेल्को तथा कान्ड्रा में क्रमशः १० प्रतिशत तथा २० प्रतिशत बोनस दिलाया गया। बिहार शरीफ में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़वायी गयी। विद्युत विभाग में ७०० मस्टर रोल को रेगुलर कराने तथा ७० जूनियर एकाउन्ट्स क्लर्क अपरेन्टिस को पुनः काम पर लाने में सफलता मिली।

बंगाल

सीटू एवं मार्क्सवादी सरकार के पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण शेष सभी श्रम संगठनों का एक जुट मोर्चा बना, फलस्वरूप कर्मचारियों की अनेक मांगे पूरी हुयीं तथा भारतीय मजदूर संघ को भी उसमें प्रतिनिधित्व देना पड़ा। जूट, इन्जीनियरिंग तथा टेक्सटाइल में लम्बे संघर्ष के बाद आवास भत्ता में बढ़ोत्तरी, वेतन में ७० रुपये मासिक बढ़ोत्तरी, ग्रेच्युटी के भुगतान आदि में सफलता मिली। ग्लोब डिटेक्टिव एजेन्सी में यूनियन के प्रयास से निकाले गए कर्मचारी काम पर वापस आए तथा वेतन में बृद्धि करायी गयी। ब्रास आर्ट्स लि० में ७० रुपये मासिक वेतन वृद्धि तथा रावल रबर वर्क्स में २० प्रतिशत बोनस तथा २.५ प्रतिशत एक्सग्रेसिया दिलाने में सफलता मिली।

उड़ीसा

राउरकेला स्थित आटो इण्डिया में संघर्ष तथा २३ दिन की तालाबन्दी के उपरान्त समझौता हुआ, जिसमें अपनी यूनियन के प्रयास से १५ रुपये वार्षिक बढ़ोत्तरी तथा ३० रुपये मूल वेतन में मासिक वृद्धि कराई गयी।

आसाम

गौहाटी स्थित अनेक कारखाने की तालाबन्दी समाप्त करने एवं मजदूरों की उचित मांगों को स्वीकार करने की मांग लेकर ७ नवम्बर ७९ को विधान भवन पर विशाल प्रदर्शन किया गया। फलस्वरूप अधिकांश मांगों को पूरा करने में सफलता मिली। चाय बागान में अनेक स्थानों पर मालिकों की ज्यादती, मजदूरों की मांग में पुलिस द्वारा फौजदारी के मुकदमे कायम करने, जबरन पैसे काटकर इनटक की यूनियन में जमा करने आदि गन्दे कारनामे जो आजादी के साथ से अब तक चले आ रहे थे, उसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने जबरदस्त आन्दोलनात्मक कदम उठाकर अधिकांश में सफलता पायी है। चण्डी घाट चाय बागान में

मजदूरों ने ३ मास तक आन्दोलन करके, महिलाओं ने घेराव करके जहाँ पुलिस द्वारा जारी किये अनेक फौजदारी की धाराओं से मुक्ति पायी हैं, वहीं सभी निकाले गये मजदूरों को काम पर वापस रखाने, यूनियन को मान्यता देने तथा २० प्रतिशत बोनस प्राप्त करने में भी सफलता पायी है। सेन्ट्रल इनलैन्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन में द्विपक्षीय वार्ता द्वारा वेतन का पुनरीक्षण कराया गया है। एसोसियेटेड इन्डस्ट्रीज श्रमिक यूनियन चन्द्रपुर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के स्तर का बोनस एवं वेतन क्रम पर एवार्ड जीता है, यद्यपि प्रबन्धक वर्ग अभी न्यायालय की शरण लिए हुए हैं।

कर्नाटक

बंगलौर स्थित स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच लि० में ३ महीने तक आन्दोलन करके उस मल्टी नेशनल फार्मास्युटिकल में ट्रेड यूनियन अधिकार दिलाया गया है तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करायी गयी है। कर्नाटक एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन में १७ दिन हड़ताल एवं विधान सभा के सामने प्रदर्शन करके पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के कार्य को सरकार द्वारा स्वीकार कराकर उसके निराकरण का प्रयास किया गया। मैसूर स्टोन पाइप्स तथा पाटरीज में १० महीने संघर्ष करके न्यूनतम वेतन तय कराया गया। सिनेमा मजदूरों ने फिल्मोत्सव के अवसर पर राजभवन पर प्रदर्शन करके अपने वेतन को बढ़वाया है।

केरल

कोचीन पोर्ट में हड़ताल करके रोस्टर आफ पद्धति को समाप्त कराया गया। प्रीमियर काटन मिल्स, पालघाट में आन्दोलन करके ३६ प्रतिशत बोनस दिलाया गया। कालीकट में अपना प्रभावी कार्य है।

तामिलनाडु

दक्षिण रेलवे कार्मिक संघ का कार्य सभी इकाइयों व मंडलों तक पहुँचा है। कैजुअल मजदूरों के संगठन को प्रभावी बनाकर उनके नियमितीकरण के लिए आन्दोलन किये गये। आवाड़ी के हैवी व्हैकिल्स फैक्टरी में अपनी प्रभावी यूनियन है।

आंध्र प्रदेश

गुन्टूर माइका में हड़ताल करके वेतन वृद्धि करायी गयी। होटल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कराने में सफलता मिली। हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज में धरना देकर वेतन बढ़ोत्तरी करायी गयी।

रजत जयन्ती महोत्सव

भारतीय मजदूर संघ ने २५ वर्ष पूर्ण कर लिया है। इस उपलक्ष में देश के कोने कोने में सम्बन्धित इकाइयों व यूनियनों ने दि० २३ जुलाई ८० के दिन भव्य आयोजन किये। अधिकांश स्थानों पर रोशनी व सजावट के साथ ही रजत जयन्ती के बिल्ले लगाकर जुलूस निकाले गये और बड़ी बड़ी रैलियां की गयीं। इस अवसर पर कुछ स्थानों पर अलग ले महिला सम्मेलन भी हुये।

उक्त कार्य-क्रमों के कारण सर्वत्र उत्साह में वृद्धि हुयी है तथा कार्य को गति मिली है।

कृषि क्षेत्र

पूर्व निश्चय के अनुसार इस अवधि में खेतिहर मजदूरों व फार्म में सेवारत मजदूरों की अनेक यूनियनों का गठन किया गया। भारतीय खेतिहर मजदूर महासंघ ने जोर शोर से कार्य बढ़ाने हेतु योजना बनाई है। अपने देश में कृषि ही अर्थ व्यवस्था की मूल धुरी है। इसलिये इस आधार भूत क्षेत्र में अपनी शक्ति को केन्द्रित करना है तथा बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता भी है। उक्त अपने महासंघ को जहां खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित त्रिदलीय समितियों में प्रतिनिधित्व मिला है, वहीं उनके सम्बन्ध में निर्मित होने वाले बिधेयक की रूप रेखा बनाने के योगदान में भी सरकार ने इसे प्रतिनिधित्व दिया है।

राष्ट्रीय श्रम दिवस

इतने वर्षों के पश्चात् राष्ट्रीय श्रम दिवस की हमारी कल्पना व रचना ने साकार रूप धारण कर लिया है। उसकी जड़ें जनता विशेषकर मजदूरों में जम चुकी हैं। गत वर्ष व इस वर्ष भी समूचे देश में विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर १७ सितम्बर को अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय श्रम दिवस के बृहद् आयोजन सम्पन्न हुये हैं। इस अवसर पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने 'डी कैजुअलाइजेशन डे'

'कैजुअल प्रथा समाप्त करो' दिवस के रूप में मनाया है। तामिलनाडु में राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर बुनकरों की दयनीय दशा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया।

बंगलौर के राष्ट्रीय श्रम दिवस के उपलक्ष में आयोजित समारोह में भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री वी० के० आर० वी० राव प्रमुख अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों को अपने आपको उद्योग का एक अंग मानना चाहिए। कानपुर के समारोह की अध्यक्षता हिन्द मजदूर सभा के नेता श्री मकबूल अहमद ने की तथा इस दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी करने की मांग की गयी। पूना में यह समारोह पूरे एक सप्ताह तक मनाया गया, जिसमें प्रतिदिन समाज के एक-एक वर्ग को इस आयोजन में बुलाकर उनके विचारों को सुना गया।

भारत का मजदूर जहां इस दिवस को स्वाभाविक रूप से, परम्परागत स्वीकार किया है, वहीं पश्चिमी रीति-रिवाजों से प्रभावित अन्य ट्रेड यूनियन नेताओं में भी क्रमशः इस दिवस की महत्ता समझ में आना प्रारम्भ हुयी है। हमारा प्रयास यही होगा कि ऐसे श्रम संगठन भी सहज रूप से इस दिवस को स्वीकार करें।

प्रदेशों की राजधानियों में विशाल प्रदर्शन

भारतीय मजदूर संघ ने अपने रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मार्च मास में सभी राज्यों की राजधानियों में जुलूस व प्रदर्शन आयोजित कर, राज्यपालों व मुख्य मन्त्रियों को आम मजदूरों तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों की समस्याओं के अलग-अलग ज्ञापन प्रस्तुत किये उनमें प्रमुख मांगें हैं :-

१- बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक तथा बढ़ती कीमतों के प्रभाव के शत प्रतिशत निवारण हेतु मंहगाई सूचक अंक के निर्धारण के सूत्र में संशोधन ।

२- सभी वेतन भोगियों को विलम्बित वेतन के रूप में ८.३३ प्रतिशत बोनस की अदायगी तथा अधिकतम बोनस की सीमा की समाप्ति ।

३- कैजुअल लेबर, मस्टर रोल तथा वर्कचार्ज मजदूरों का नियमितीकरण ।

४- एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून ।

५- ग्रामीण, खेतिहर तथा वन व्यवसायों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून ।

६- सभी प्रकार के मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन ।

७- आय, वेतन, उत्पादकता, मूल्य, रोजगार तथा पूंजी विनियोग पर राष्ट्रीय नीति निर्धारण हेतु सभी सम्बन्धित आर्थिक पक्षों का गोलमेज सम्मेलन ।

८- सामूहिक सौदेबाजी पर लगे अंकुशों की समाप्ति ।

९- उद्योगों का श्रमिकीकरण । प्रारम्भिक रूप में मजदूरों की भागीदारी ।

१०- राज्य विधान मंडलों तथा संसद में व्यवसायिक प्रतिनिधित्व ।

११– 'विश्वकर्मा दिवस' को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मान्यता।

१२– भारतीय मजदूर संघ को अखिल भारतीय मान्यता।

मार्च १९८० की विभिन्न तिथियों में देश की राजधानियों अर्थात् जम्मू, चण्डीगढ़, दिल्ली, जयपुर, शिमला, भोपाल, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, भुवनेश्वर, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, नागपुर तथा बम्बई में आयोजित प्रदर्शनों में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, खानों तथा कारखानों के मजदूरों, ग्रामीण खेतिहर मजदूरो तथा वनवासी श्रमिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पटना, भोपाल, जयपुर, बंगलौर तथा बम्बई के प्रदर्शनों में महिला मजदूरों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। पटना के जुलूस में कोयला खान कर्मचारी बैट्री बल्बों से युक्त टोप लगाकर चल रहे थे। जयपुर के जुलूस की विशेषता थी-झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं की बड़ी संख्या में भाग लेना। लखनऊ के जुलूस में खेतिहर तथा वनवासी मजदूरों की प्रभावी सख्या थी। बम्बई के जुलूस में घरेलू कामगारों की अनोखी यूनियन के सदस्यों ने पर्याप्त सख्या में भाग लिया। जम्मू, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद तथा भुवनेश्वर के जुलूसों में जहाँ कम से कम हजार से तीन हजार तक मजदूर थे, वही बम्बई तथा लखनऊ के जुलूस में ३०००० मजदूरों से अधिक की संख्या थी। इन जुलूसों में कुल एक लाख पचास हजार मजदूरों ने भाग लिया।

सभी जुलूसों में मजदूर भारतीय मजदूर संघ के भगवा झडे तथा अपने अपने औद्योगिक महासंघों तथा यूनियनों के नाम पट लिये नारे लगाते हुये चल रहे थे। प्रमुख नारे थे 'भारत माता की जय'। 'देश के हित में करेंगे काम-काम के लेंगे पूरे दाम,' 'उत्पादकता बोनस धोखा है – धोखा है,' 'आय विषमता समाप्त हो एक दस अनुपात हो,' 'आटोमेशन- एन्टीनेशन,' 'देश की रक्षा पहला काम–सबको काम बाघो दाम।'

अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, चण्डीगढ़, हैदराबाद तथा बम्बई के जुलूसों का नेतृत्व श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी ने किया। अन्य स्थानों पर सर्वश्री नरेश चन्द्र गांगुली, रामनरेशसिंह, बालासाहब साठ्ये, प्रभाकर घाटे, रमणशाह, ओमप्रकाश आग्घी, रामप्रकाश मिश्र, गोविन्दराव आठवले, राजकृष्ण भक्त तथा रासबिहारी मैत्र ने नेतृत्व किया।

भारतीय मजदूर संघ की इकाइयां

रजत जयन्ती वर्ष के दौरान भारतीय मजदूर संघ की नगर व जिला समितियों की संख्या १५० करने के साथ ही सम्बद्ध यूनियनों की संख्या २५०० एवं सदस्य संख्या २५ लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें इस लक्ष्य की २३ जुलाई १९८१ के अन्दर पूर्ति करनी है।

भारतीय मजदूर संघ निधि

जयपुर अधिवेशन के समय सम्बद्ध यूनियनों के प्रत्येक सदस्य से भारतीय मजदूर संघ के कोष हेतु हमने अपील की थी, फलस्वरूप सन्तोषजनक स्थिति में लोगों ने प्रतिसाद दिया, जिससे आर्थिक स्थिति मे सुधार सम्भव हो पाया।

मंहगाई विरोधी पखवारा

राष्ट्रीय श्रम दिवस १९८० में प्रारम्भ हुए पखवारे तथा २ अक्टूबर से आरम्भ हुए पखवारे में सम्बद्ध यूनियनों ने समूचे देश में मंहगाई विरोधी पखवारा मनाया। इस प्रकार कुल ५०० से भी अधिक स्थानों पर जुलूस, धरने व रैलियों के वृहद आयोजन सम्पन्न हुए।

राहत कार्य

प्राकृतिक प्रकोप से त्रस्त मोरवी (गुजरात) व विदर्भ के बाढ़ पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गयी।

समितियों के निर्वाचनों में सफलतायें एवं प्रतिनिधित्व

प्रतिरक्षा संस्थान में कई स्थानों की वर्क्स कमेटियों व अन्यान्य कमेटियों में अपनी यूनियनों ने विजय प्राप्त की है। कानपुर की एस० ए० एफ० में १० सीटों में से ९, कैन्टीन में ४ सीटों में सभी, सी० आई० एम० कानपुर, में ४ में २, डी०एम०एस०आर०एम०ई० कानपुर में ६ में ४, शाहजहांपुर, अम्बरनाथ तथा मुरादनगर की आर्डिनेन्स फैक्टरियों की वर्क्स कमेटियों में क्रमशः १० में ५, ७ में ४, तथा १० में ५ सीटें जीती हैं। सी० ओ० डी० आगरा में १० में ९, डी० जी० आई० कम्पलेक्स कानपुर में १९ से १०, वेहिक्लि फैक्टरी जबलपुर में १० में ७, अम्बाझरी में २, चन्द्रपुर में ५ सीटे जीती हैं तथा आर्डनेन्स डिपो शकूर बस्ती

दिल्ली में ३२ प्रतिशत मत प्राप्त करके इनटक व एटक समर्थित यूनियनों को पीछे ढकेल दिया है।

अभी हाल ही में दिनांक ५ दिसम्बर १९८० के वर्क्स कमेटी के चुनाव में बंगलौर स्थित बी० इ० एल० की अपनी यूनियन को अन्य यूनियनों से सर्वाधिक ३३०७ मत मिले तथा ८ सीटों में २ पर विजय पायी एवं ४ तथा २१ वोटों से २ पर पराजित हुए। झांसी मध्य रेलवे में १४ स्थानों में से ३ स्थान ई० सी० सी० में मिले।

२१ जनवरी, १९८१ को आयोजित बीड़ी एवं सिगार मजदूरों के त्रिदलीय सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व मिला है।

उड़ीसा की अपनी यच०एस०सी०एल० की यूनियन मान्यता प्राप्त है। राजस्थान के खेतड़ी के कापर्स, अजमेर की एच०एम०टी०, सहकारी मिल गुलाबपुरा में चुनाव जीते और इन्हें सबसे बड़ी यूनियनों के रूप में मान्यता मिली है। ओ०टी०जे० पठानकोट के वर्क्स कमेटी चुनाव में सभी सीटों पर विजय मिली। मिलीटरी फार्म जालन्धर में बहुमत से विजयी हुए। फीरोजपुर मिलीटरी फार्म में सभी सीटें जीती। नांगल के फर्टीलाइजर कारखाने में ७ में से वर्क्स कमेटी में ३ स्थानों पर सफलता मिली।

कर्नाटक प्रदेश मजदूर संघ को क्षेत्रीय भविष्य निधि कमेटी तथा फोरमेन्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में केन्द्रीय सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया है।

ग्वालियर रियान्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी मावूर की कोआपरेटिव सोसाइटी में १ डाइरेक्टर, मालावार स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कालीकट में १ डाइरेक्टर तथा कैन्टीन कमेटी में एक सदस्य विजयी हुआ। नवल फिजीकल तथा ओसनोग्राफिक लेबरोटरीज की वर्क्स कमेटी की सभी सीटें जीत ली। एम० इ० एस० कोचीन में २ तथा कोचीन ट्रस्ट की वर्क्स कमेटी में एक सीट जीती।

केन्द्रीय अप्रेन्टिस कमेटी तथा जूट की दोनों कमेटियों में भारतीय जूट मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व मिला है। हुकुमचन्द्र जूट मिल रिलायांस जूट मिल, नफरचन्द्र जूट मिल एवं एंग्लो इन्डिया जूट की वर्क्स कमेटियों के चुनावों में अपने प्रतिनिधि बहुमत से जीत कर आये।

कोचीन स्थित यन० पी० ओ० एल० की वर्क्स कमेटी की सभी सीटें, एम० इ० एस० की २ तथा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की एक सीट जीती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा गोष्ठियां

जब १९७७ में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कामगारों के प्रतिनिधित्व का विस्तार करने का विचार किया तो अन्य संगठनों के साथ ही भारतीय मजदूर संघ को स्थान मिला। इस तरह तिरसठवें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जो १९७७ में जेनेवा में हुआ था, इसमें भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने किया तथा १९७८-७९ में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री श्री जी प्रभाकर ने प्रतिनिधि मंडल में सलाहकार की हैसियत से भाग लिया।

१९८० में वर्तमान सरकार ने श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों में से 'क्रम से चयन करने के सिद्धांतो' के अनुसार जैसा कि जापान, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों में किया जाता है और जैसा अपने देश में सेवायोजकों के प्रतिनिधियों को चुनने में होता है, ऐसा न करके केवल इनटक के आदमियों को ही कामगारों के दल में पूरी तरह से स्थान देने की पुरानी नीति की पुनरावृत्ति की।

भारतीय मजदूर संघ अन्य केन्द्रीय श्रम संगठनों के साथ अभी भी यह निरन्तर प्रयास कर रहा है कि सरकार श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चयन में 'चक्रीय विधि' स्वीकार करे। इटली के तूरीन नामक स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राविधिक संस्थान में ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों का दीक्षा का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। तीन बार इस संस्थान से भारतीय मजदूर संघ को अपने नामांकित व्यक्तियों को भेजने का निमन्त्रण आया। इस सत्र में भाग लेने के लिये संघ ने १९७८ में श्री एम० जी० डोगरे को, १९७९ में श्री रामप्रसाद पारिख को तथा १९८० में श्री बैजनाथ राय को भेजा। खेतिहर मजदूरों को संगठित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में वाराणसी में हुई एक गोष्ठी में भी श्री एम० जी० डोगरे तथा श्री रामप्रकाश मिश्र ने भाग लिया।

१९७९ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित त्रिवेन्द्रम में एशियाई क्षेत्रीय गोष्ठी में भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व श्री जी प्रभाकर ने किया।

दिल्ली में यूगोस्लाविया के अनुभव के आधार पर औद्योगिक प्रबन्ध के संबंध में आयोजित एक गोष्ठी में श्री एन०सी० गांगुली तथा श्री बी० एन० साठे ने भाग लिया।

उक्त कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट क्र० ४ में दिया गया है।

मा० श्री ठेंगड़ी जी की अमेरिका यात्रा

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के निमंत्रण पर श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने अमरीकी राज्यों का विस्तृत दौरा किया तथा अमेरिकन ट्रेड यूनियन संगठन, अमेरिकन फेडरेशन आँफ लेबर सी० आई० ओ० के कार्य प्रणाली का निकट से अध्ययन किया। अपने एक माह के प्रवास में अमरीकी श्रम संगठनों को बहुत नजदीक से देखा तथा वहां के नेताओं और कामगारों के सम्पर्क में आये। इस प्रवास के परिणाम स्वरूप अमेरिका में श्रम सगठन आंदोलन का विशिष्ट राजनीतिक स्वरूप उभर कर सामने आया।

शिक्षा तथा दीक्षा

अपने कार्य के विस्तार की दृष्टि से कार्यकर्ताओं में समर्पण–भावना की वृद्धि तथा निरन्तर अपने मार्ग पर सही दिशा में बढ़ते रहने के दृष्टिकोण से विभिन्न स्तरों पर दी गयी अपने कार्यकर्त्ताओं की दीक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय स्तर पर १९८० में पुणे में पांच दिन का शिक्षा वर्ग चलाया गया, जिसमें पाच सौ सक्रिय कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। हमारे संगठन की प्रगति के लिये यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटना है। शिक्षा वर्ग में श्री ठेंगड़ी जी के ज्ञान वर्धक और विचार प्रेरक व्याख्यानों को एक पुस्तकाकार 'विचार सूत्र' में निकाला गया है, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिये एक विशिष्ट दिशा निर्देश के रूप में उपयोगी होगी। हमारा विश्वास है कि इन लिपिबद्ध व्याख्यानों में निहित सामग्री हमारे कार्यकर्ताओं के लिये अनेक वर्षों तक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। भविष्य में हम ऐसे और कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रयास करेंगे।

नगर, जिले तथा प्रदेश के स्तर पर तो अनेकानेक शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम सम्पन्न हो चुके है।

कामगार शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम तथा गोष्ठियाँ

बम्बई में समय-समय पर कामगार शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों तथा विभिन्न पाठयक्रमों में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का अधिकाधिक योगदान होता रहा है। एक ऐसा कार्यक्रम तो विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों, कार्यालय मन्त्रियों तथा कोषाध्यक्षों के लिये चलाया गया। दिग्गज ट्रेड यूनियनिष्ठ श्री एन. एम. जोशी की शताब्दी पर संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी (ट्रेड यूनियन आज और कल) में हमारे वित्त सचिव श्री एम. पी. मेहता ने प्रभावी रूप से भाग लिया। विशेष रूप से महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्रियों के लिये आयोजित एक पाठ्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ की ओर से पांच सक्रिय महिला कार्यकर्त्रियों ने भाग लिया।

पाठयक्रमों तथा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं की संख्या जिन्होने इसमें भाग लिया, परिशिष्ट क्र० ५ में दिया गया है।

कार्य समिति की बैठकें

इस कार्यावधि में भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की आठ बार बैठकें हुयीं जैसा परिशिष्ट क्र० ६ से स्पष्ट है।

संगठनात्मक प्रवास

हमारे विभिन्न सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संगठनात्मक प्रवास के परिणामस्वरूप हमारे संगठन का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। आपने अनेक अन्य उत्तरदायित्वों के होते हुये भी श्री ठेंगड़ी जी सम्पूर्ण देश में निरन्तर प्रवास करते रहे हैं। इन संगठनात्मक प्रवासों को चलाने में केवल संगठन मन्त्री श्री साठे जी ने ही नहीं, बल्कि अन्य पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय मन्त्रियों ने भी मुझे सहयोग दिया है। औद्योगिक महासंघों के पदाधिकारियों ने भी इस दिशा में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि इनसे हमारी इकाइयां बहुत लाभान्वित हुई होगी। हमारे कार्य की बढ़ती हुई स्थिति इसका सजीव उदाहरण है। अस्तु यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे सक्रिय कार्यकर्ता निरन्तर भ्रमण करते रहें। कार्यकर्त्ताओं से निरन्तर सम्पर्क स्थापित रखें तथा कार्य के विस्तार में सहायक बनें। हमारे कार्यकलापों का यह अंग काफी महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय कार्यालय तथा पूर्ण कालिक कार्यकर्त्ता

केन्द्रीय कार्यालय को अधिक सशक्त तथा प्रभावी बनाने का प्रयास निरंतर चलता रहा है। आप सभी को केन्द्रीय कार्यालय से त्वरित उत्तर प्राप्त होने का अनुभव हुआ होगा। हमारे अखिल भारतीय मन्त्रियों में से एक श्री ओमप्रकाश अग्गी, जो रेजीडेंट सेक्रेटरी की हैसियत से केन्द्रीय कार्यालय के कार्यकलापों की देखभाल भी करते हैं। श्री प्रेमनाथ शर्मा, कार्यालय मन्त्री को कार्यालय के कार्य का लम्बा अनुभव है। श्री जी डी. सोहनी केन्द्रीय कार्यालय में स्थित भारतीय रेलवे मजदूर संघ उप केन्द्रीय कार्यालय का कार्य देख रहे हैं तथा केन्द्रीय कार्यालय चलाने में श्री शर्मा को सहयोग भी करते हैं। सेवा निवृत्त अधिकारी श्री बी. डी. फड़के ने स्वेच्छा से हमारे लिये कार्य करना स्वीकार किया है। हाल ही में उडीपी के जीवन बीमा निगम के कर्मचारी श्री जे० आर० भट्ट ने अपनी सेवा से त्यागपत्र देकर भारतीय मजदूर संघ के कार्य के लिये अपने को अर्पित किया है तथा वे हमारे केन्द्रीय कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक टंकण तथा एक सहायक कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय कार्यालय में बढ़ते हुए काम को देखते हुए यह सब प्रबन्ध अपर्याप्त प्रतीत होता है तथा हम उपयुक्त व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या द्वारा कार्यालय को सज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु यह सब कुछ अन्ततोगत्वा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने में से लगन तथा त्याग की भावना से सम्पन्न और अधिक कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय कार्यालय की आवश्यकता के लिये लगायें।

जयपुर सम्मेलन के समय अपने पूर्ण कालिक कार्यकर्त्ताओं की संख्या १५३ थी, जो अब बढ़कर १७५ हो गई है। पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता ही हमारे कार्य के सूत्रधार हैं। उनमें से अधिकांश उन उद्योगों से आये हैं, जहां भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें सक्रिय रही हैं, इन लोगों ने अपने सेवाकाल में ही अपने उद्योगों तथा नगरों में भा० म० संघ की यूनियनों का प्रारम्भ किया तथा उसका बिस्तार किया। जब उन्होंने देखा कि पूरी लगन से दो स्थानों पर कार्य नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारतीय मजदूर संघ के प्रति उनके इस प्रेम ने ही इस उदात्त कार्य के लिये उन्हें अपना जीवन समर्पित करने के लिये प्रेरित किया।

हम आपका विशेष ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि दिल्ली में श्री वी. डी. फड़के तथा श्री जे. आर. भट्ट पूना में श्री बी. आर. गोखले

और श्री आप्टे, बम्बई में श्री तमहंनकर तथा श्री बिलवालकर, पंजाब में श्री एच. एन. विश्वास तथा श्री आर. के. भक्त, पश्चिम रेलवे आगरा के श्री लोकनाथ अपनी लम्बी तथा यशस्वी सेवा अवधि के पश्चात् भारतीय मजदूर संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करने के लिये अग्रसर हुए हैं। देश में अनेक ऐसे दूसरे लोग हैं, जो एक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में है, जबकि अपनी सेवा से समय से पूर्व भी आवश्यकतानुसार सेवा अवकाश लेकर भारतीय मजदूर संघ के काम में लगने वाले हैं। यह उचित है कि हम इस प्रक्रिया को बढ़ावा दें तथा ऐसे सभी लोगों को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सेवा करने का अवसर दें, जो अपने सारे जीवन के लिये उन्हे प्रिय वस्तु हैं।

केन्द्रीय पुस्तकालय

इस कार्यविधि में केन्द्रीय कार्यालय ने एक पुस्तकालय का लगभग २५० से अधिक पुस्तकें जोड़कर विकास किया है। निकट भविष्य में हम इस पुस्तकालय को रिफरेंस लाइब्रेरी की मांग की पूर्ति के योग्य क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

हमारे अनेक प्रदेशीय राजधानियों तथा केन्द्रों से अनेक पत्रिका प्रकाशित होती हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट क्र० ३ में दी गई है।

श्रम अन्वेषण केन्द्र

यह सन्तोष का विषय है कि जनवरी १९८० में पुनर्गठित करने के पश्चात् भारतीय श्रम अन्वेषण केन्द्र अधिक सक्रिय हुआ है। "विचार सूत्र" तथा "इन्डस्ट्रियल रिलेशन एब्रोड" नामक प्रकाशनों का श्रेय इसी केन्द्र को है।

कामगर शिक्षा संस्थान

अपने संगठन द्वारा एक कामगर शिक्षा संस्थान प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है। हमारे एक क्षेत्रीय मन्त्री श्री गोविन्दराव आठवले अभी इस प्रस्ताव की रूपरेखा तय्यार कर रहे हैं।

●

भारतीय मजदूर संघ की माँगे

सरकार द्वारा श्रमनीति को तय करने में देरी व गत्यावरोध राष्ट्र के लिये घातक है। यह गत्यावरोध सरकार की आनिश्चित मनःस्थिति के साथ ही श्रम विरोधी भी है। जब तक इसका अन्त करके कामगारों को न्याय तथा राष्ट्र जीवन में समुचित सम्मानित स्थान नहीं दिया जाता, संघ की मांग है कि सरकार श्रमिकों के प्रति अपने दृष्टि कोण में आमूलचूल परिवर्तन लाये तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में उनकी महत्ता तथा विशिष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए आपेक्षित श्रम नीति अपनायें। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि केन्द्रिय श्रम विभाग कैबिनेट स्तर के किसी वरिष्ट मंत्री को ही सौंपा जाय, जिसके पास किसी अन्य विभाग का दायित्व न रहे।

अतीत का यही अनुभव रहा है कि श्रम मंत्रालय की आवाज हमेशा कमजोर रहने के कारण प्रतिरक्षा, उद्योग तथा संचार आदि सेवायोजक मंत्रालयों के प्रभाव के कारण दबी रही है तथा श्रमिकों को न्याय दिलाने में श्रम मंत्रालय सक्षम नहीं रहा है। यह स्थिति अब पूर्णतया असह्य हो उठी है। श्रम सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेते समय श्रमिकों की राय का सर्वाधिक महत्व है। इस दिशा में भारतीय मजदूर संघ आशा करता है कि सरकार शीघ्र ही एक स्पष्ट श्रम नीति की घोषणा करेगी।

एक ठोस औद्योगिक श्रम प्रणाली की एक अर्से से प्रतीक्षा रही है। एक वर्ष के शासन काल के बाद भी सरकार किसी औद्योगिक श्रम व्यवस्था पर विचार करती प्रतीत नहीं होती। सरकार को शीघ्र ही केन्द्रीय श्रम संगठनों से अविलम्ब वार्ता करके एक 'औद्योगिक संबंध विधेयक' बनाना चाहिये, जिसमें अतीत में इस दिशा में किये गये प्रयासों की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

एकाधिकारों तथा मूल्यों पर नियन्त्रण

आजवस्तुओं के मूल्यों की स्थिति अत्यन्त नाजुक है। सरकार का कहना

है कि मूल्यों में गिरावट आ रही है, विश्वास नहीं किया जा सकता। मूल्य वृद्धि से गरीब जनता तथा मजदूर बुरी तरह पीड़ित है। इससे केवल एकाधिकारियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा ऐसे ही लोगों को लाभ हुआ है। इस क्षेत्र में जब तक प्रभावी कदम नहीं उठाये जाते, मूल्यों पर नियंत्रण सम्भव नहीं है। इस दिशा में सरकार को बिना समय गवायें, तुरन्त निश्चित कदम उठाना चाहिये।

यह निश्चित है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में तभी सुधार हो सकता है व स्थिरता आ सकती है, जब उत्पादन में वृद्धि हो। इस उद्देश्य की पूर्ति में मजदूर व कामगार कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। इसके लिये श्रम कानूनों पर नये सिरे से पुनर्विचार के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, जो कानून अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, उन्हें रद्द कर नये कानून बनाने चाहिये। जिन धाराओं को संशोधित करना आवश्यक हैं, उनको फिरसे बनाकर एक वृहद 'श्रम अधिनियम' का निर्माण करना आज समय की पुकार है।

कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

श्रमिकों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियमों के क्षेत्र विस्तृत करके सभी प्रकार के मजदूरों को इनके द्वारा लाभ दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार बोनस अधिनियम, इम्पलाइज प्राविडेण्ट फण्ड अधिनियम तथा ग्रैच्युटी एक्ट आदि सभी वेतन भोगियों पर लागू होने चाहिए। बोनस-विलम्बित वेतन है, के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिये।

इम्पलाइज प्राविडेण्ड फण्ड स्कीम को धीरे २ समुचिय पेंशन स्कीम में इस प्रकार बदलना चाहिये कि व्यक्ति विशेष को देय पेंशन की धनराशि मूल्य सूचनांक से जोड़ी जाय तथा पेंशन पाने वाले की इच्छानुसार पेंशन की सम्पूर्ण अथवा आंशिक राशि का विनियोग हो।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की निगम द्वारा कुशलता से व्यवस्था की जानी चाहिये। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने लम्बे चौड़े ढ़ांचे के कारण प्रभावी नहीं हो पा रहा है। उसका नये सिरे से गठन होना चाहिये।

जहां हम मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को उनके मौलिक अधिकार के रूपमें सुरक्षित रखने के घोर हिमायती हैं वहीं भारतीय मजदूर संघ यह मांग

करता है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुये, समस्त अनिवार्य आवश्यक सेवा संस्थानों में ऐसी प्रभावी अतिरिक्त व्यवस्था औद्योगिक विवादों को हल करने के लिये उपलब्ध होनी चाहिये, जिससे हड़ताल करना आवश्यक प्रतीत हो ।

बर्कमेन्स कम्पेनसेशन अधिनियम क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए तथा इसकी सूची में समग्ररूप से व्यवसायिक रोगों तथा उसके खतरों को सम्मिलित करना चाहिये ।

न्यूनतम वेतन असंगठित क्षेत्र के सभी प्रकार के व्यवसायों के लिये लागू होना चाहिए, इसे जीवन मूल्य सूचकांक से जोड़ना चाहिये । जो उद्योग या व्यवसाय दो या अधिक राज्यों में फैले हैं, उनमें सेवारत कर्मचारियों का समान न्यूनतम वेतन होना चाहिए ।

श्रमिकों की सलाह से उद्योगों में उनकी पूर्ण क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना चाहिये ।

मजदूरों की प्रबंध में साझेदारी दिखावे मात्र के लिये नहीं होनी चाहिये । इसका सार्थक रूप कियान्वित करना चाहिए । जिसका अन्तिम उद्देश्य उद्योगों में मजदूरों का स्वामित्व से प्रतिफलित होना चाहिये, जिसे भारतीय मजदूर संघ 'श्रमकीकरण' के नाम से पुकारता है ।

कुशल वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बहुत असन्तोष जनक रही है । इसकी कुशलता में तथा इसके क्षेव में सुधार अनिवार्य है । भारतीय मजदूर संघ यह सुझाव देता रहा है कि वितरण व्यवस्था का निरीक्षण जन समितियों द्वारा होना चाहिये, जिसमें मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व हो ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

बहुराष्ट्रीय संस्थायें हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण करती रही हैं । उनसे होने वाले समझौतों में ऐसी शर्तें होनी चाहिये, जो हमारे देश के लिए हितकर हों । सरकार को यह भी देखना चाहिये कि विदेशों से हुए समझौतों में हमारे अधिकारों को सीमित करने वाली धारायें निरस्त हों ।

६ठीं पंचवर्षीय योजना

जब ६ठीं पंचवर्षीय योजना अभी बनाई जा रही है तो हम अपने पूर्व से व्यक्त किये गये उस विचार को फिर से दुहराते हैं कि सरकार को सभी आर्थिक हित पक्षों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाकर रोजगार, उत्पादन, उत्पादकता, पूँजीनिवेश, मूल्य, आय/वेतन आदि पर विस्तृत व राष्ट्रीय आर्थिक नीति को आम सहमति से तय करनी चाहिये तथा इस आधार पर ही पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिये।

सरकार को एक ऐसा तरीका भी निकालना चाहिए, जिससे बेरोजगारी तथा गरीबी का सही मूल्यांकन हो सके।

खेती के उत्पाद्य पदार्थों का लागत मूल्य

सरकार को खेती में लगाये जाने वाले, समस्त पदार्थों जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिजली, पानी को कम दर पर देना चाहिये तथा सीमान्त कृषकों को व्यापक स्तर पर ऋण देना चाहिए। इससे खेती के उत्पादों का मूल्य कम होगा तथा खेतिहर किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा और उपभोक्ता को उनकी खरीदी हुई वस्तुओं पर अधिक मूल्य नहीं देने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो इस प्रकार अतिरिक्त धन लगाया जायगा, उससे अन्यान्य ग्रामीण उद्योग शुरू किए जा सकेंगे तथा भूमि पर दबाव कम हो सकेगा और रोजगार के नये श्रोत प्राप्त होंगे। इससे कृषकों द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उचित मजदूरी देने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

व्यापक श्रम अधनियिम

वर्तमान परिपेक्ष में अधिकांश श्रम अधिनियम अपनी उपादेयता खो चुके हैं। ये हमारे राष्ट्रीय व आर्थिक विकास में श्रमिकों की साझेदारी के स्वरूप तथा आधुनिक सिद्धांतों का सही चित्रण नहीं करते हैं।

त्रिदलीय सम्मेलन

त्रिदलीय सम्मेलन का सिद्धान्त व्यापक रूप से माना जाना चाहिये तथा

उनका वास्तविक स्वरूप विकसित करके उन सभी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय श्रम संगठनों को उनमें प्रतिनिधित्व देना चाहिये, जो श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। यही पद्धति राज्य तथा अन्य नीचे तक के स्तरों पर लागू किया जाना चाहिये।

इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड, इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स, मजदूरों की शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित समितियों में भारतीय मजदूर संघ को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सरकार को तटस्थ रहना चाहिये

सरकार को अब तक एक श्रम संगठन 'इण्टक' को ही बढ़ावा देने की नीति त्यागनी चाहिए तथा ट्रेड यूनियन के मामले में वास्तविक तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए।

महिला मजदूर

विषम होती आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण अधिक महिलाएं रोजगार में आ रही हैं। उनकी सुरक्षा, कार्य में सन्तुष्टि तथा उनके कल्याण की ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए। अनेक स्थानों पर अब भी महिलाओं के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है, ऐसी प्रवृत्ति का निर्मूलन होना चाहिए। उनकी गृहस्थी की जिम्मेवारी तथा काम की जिम्मेवारी के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी विशेष आवश्यकताओं की भी चिन्ता करने की जरूरत है और इस दिशा में सरकार को अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए।

कैजुअल प्रथा बन्द हो

सरकारी उद्योगों तथा अन्य सेवाओं में कैजुअल, एन. एम. आर. तथा बर्क-चार्ज श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति विडम्बनापूर्ण है। इन नामों से केवल अन्याय तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इन सभी भेदभाव, अन्यायपूर्ण कृत्यों को अविलम्ब रोके। अपरेण्टिसों का शोषण भी बन्द होना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वापस हो

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कानून, जो प्रशासन के द्वारा लोगों पर मुकदमा चलाए बिना कैद कर लेने का अधिकार देते हैं, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि ये कानून प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

श्रम विवादों में पुलिस का हस्तक्षेप

कानून और व्यवस्था की स्थापना के नाम पर श्रम विवादों में पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ इसकी भर्त्सना करता है और सरकार से मांग करता है कि पुलिस हस्तक्षेप को रोका जाय।

सामूहिक सौदेबाजी

भारतीय मजदूर संघ, द्विपक्षीय वार्ता की पद्धति में विश्वास करता है। सरकार को पर्दे के पीछे से संचालन करने की रीति को बन्द करना चाहिए तथा ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज को सार्वजनिक संस्थाओं की समझौता वार्ता में दखलन्दाजी करने से रोकना चाहिए।

हमारा निश्चय

जयपुर सम्मेलन के बाद हम काफी प्रगति कर चुके हैं, किन्तु अभी काफी दूरी तय करनी है। जब हम पिछली बार मिले थे तो हम प्रगति के पथ पर कूच करने को तैयार थे। आज केवल हमने एक निश्चित मार्ग पर कूच ही नहीं किया, वरन सफलता की शिखर की ओर पहुँच रहे हैं। इस दशक के लिए हमारा यह लक्ष्य है कि हम इतनी तेजी से चलें तथा सफलता की उस ऊँचाई को प्राप्त करें कि अन्य संगठनों से काफी आगे बढ़ जायें और समस्त कामगारों व वेतन भोगियों का हमें विश्वास प्राप्त हो।

असंगठित मजदूरों की स्थिति

हमारे देश में संगठित मजदूर अपनी समस्याओं से निपटने के लिये सक्षम हैं। किन्तु इतने से उनके कर्तव्य की इति श्री नही हो जाती। असंगठित क्षेत्र में लाखों मजदूरों का क्या होगा ? ऐसे मजदूर केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं। प्रत्येक उद्योग में संगठित मजदूरों के साथ उनका सहअस्तित्व है। ग्रामीण व खेतिहर मजदूरों में उनका बाहुल्य है। राष्ट्र ने प्रगति की है, ऐसा नहीं कहा जा सकता जबतक कि इन लाखों मूक लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। राष्ट्र की प्रगति इन निम्न श्रेणी के गरीब लोगों की प्रगति से आंकी जानी चाहिये।

अधिक भाग्यवान व अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति के संगठित मजदूरों का इन असंगठित भाइयों की ओर ध्यान देने का विशेष कर्तव्य है। उनके उद्देश्यों की पूर्ति भी इन कम भाग्यशाली बन्धुओं के उद्देश्यों की पूर्ति से जुड़ी हुई है। इसे भूलना स्वयं को धोखा देना है। भारतीय मजदूर संघ इस सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं को समुचित निर्देश देने में अपना कर्तव्य समझता है। आप आगे आने वाले वर्षों में इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करें। उन्हें केवल सरकार की कृपा पर रहने के लिये हम न छोड़ दें, बल्कि हम स्वयं उन्हें हर सम्भव सहायता दें।

किसानों की समस्या

पिछले वर्ष एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिये अविरत संघर्ष किये हैं, यद्यपि इन संघर्षों का लाभ लेने के लिये कुछ राजनैतिक पार्टियां आगे आयी हैं। किन्तु अत्यन्त सन्तोष का विषय है कि बहुतांश किसानों ने स्वयं ही अपने संघर्ष व आन्दोलनों को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त रखने का निश्चय किया है। यह आवश्यक है कि सही ट्रेड यूनियन आन्दोलन को इस प्रकार के आन्दोलन से निकट का सम्पर्क बनाये रखना चाहिये क्योंकि उक्त दोनों प्रकार के आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, साथ ही इस प्रयास में हमें यह ध्यान रहे कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों की स्थिति में सुधार के प्रयत्न में कहीं धक्का न लगे।

मजदूरों का सम्पूर्ण विकास ही– हमारा लक्ष्य

हम अपने कार्य कलापों को संघर्षों तथा आंदोलनों द्वारा मजदूरों के लिए केवल आर्थिक लाभ दिलाने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हालांकि यह हमारे कार्य का एक महत्व पूर्ण अंग है। हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है तथा इसका उद्देश्य मात्र आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त करना ही नहीं है।

मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब प्रकार के प्रयास करेंगे। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक, ईमानदार तथा कठिन परिश्रम करने वाला समर्पित श्रमिक राष्ट्र के लिये एक पूँजी है। ऐसा ही मजदूर राष्ट्र की कुशलता तथा हितों का रक्षक बन सकता है। वह केवल अपने सीमित परिवार का सदस्य नहीं, समाज रूपी बड़े परिवार का सदस्य होने के नाते उसके कुछ कर्तव्य व उत्तरदायित्व हैं, जिसे उसे समझना चाहिये तथा इस सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जिम्मेवार, साहस तथा त्याग की भावना से परिपूर्ण व अन्य गुणों से सज्जित नागरिक ही भारत माता का सच्चा सपूत बन सकता है। आइये ! अपने ऐसे अनेकानेक क्रिया कलापों द्वारा ऐसे सपूतों का निर्माण करें।

हमें सतर्क रह कर हिंसा तथा तोड़फोड़ से बचना चाहिये। बाह्य रूप से ये लुभावने होते हैं तथा लगता है कि इससे त्वरित फल मिल सकेगा ; पर वास्तव में यह ऐसा रोग है, जो अन्ततोगत्वा उद्देश्य पूर्ति में बाधक ही होता है। इस दृष्टि

कोण के साथ ही हमें संघर्षशीलता व जुझारु प्रवृत्ति ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिये।

आज बहुत सी ऐसी खाइयाँ हैं, जिसमें मजदूर गिरकर फंस सकता है तथा अपने ट्रड यूनियन के प्रयासों को झुठलाकर बहुत सा पैसा बर्बाद कर सकता है। पीने, जुआ खेलने, पुराने जमाने के रीति रिवाजों आदि पर व्यर्थ के खर्चे दिनोंदिन बढ़ रहे हैं तथा मजदूरों के परिवारों की सामान्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ट्रेड यूनियनें उन खतरों से बचाने में प्रभावी हो सकती हैं तथा अपने सदस्यों के जीवन व जीवन यापन को और अधिक अच्छा बना सकती हैं।

काला बाजारी, रोजमर्रा की चीजों की कृत्रिम कमी, दवाओं व खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध संघर्ष चलता रहेगा, किन्तु मजदूर उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा तथा अन्य आर्थिक प्रयास से इन कमियों की पूर्ति कर सकता है। मजदूर, उपभोक्ता हित रक्षा आन्दोलन भी संगठित कर सकते हैं।

कल्याणकारी कार्यों के लिये सरकार व प्रबन्धकों पर पूरी तौर पर निर्भर रहने के बजाय औद्योगिक संघों के आवासीय सुविधा को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिये तथा मृत्यु सुरक्षित कोष का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिये व मजदूरों की बचत योजना द्वारा उन्हें आवांछनीय तत्वों से अलग रखना चाहिये। सांकेतिक रूप में ऊपर कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है कि ट्रेड यूनियनें इन कार्यों में भी प्रवेश करें। इनके साथ ही ट्रेडयूनियनों के मौलिक कार्यों द्वारा जैसे, मजदूरों को संगठित करने, आर्थिक न्याय के लिये उनके संघर्षों द्वारा ही सशक्त व स्वस्थ्य ट्रेड यूनियनों का निर्माण हो सकता है तथा वे ही उद्देश्य पूर्ण निर्देश भी दे सकती हैं।

तो आइये ! हम इस नये मार्ग पर आगे बढ़ें।

राष्ट्र निर्माण के लिये संगठन व संघर्ष

हम मजदूरों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अपना संगठन बना रहे हैं। इसके लिये हमें अभी अपने संगठन को और पुष्ट करना होगा। हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकलापों का उद्देश्य हमारी संगठनात्मक रचना को सुदृढ़ करने की होनी

चाहिए, ताकि यह सशक्त संगठन और अधिक लम्बे व कठिन संघर्षों को चला सके। संगठन व संघर्ष दो भुजाये —जिसके द्वारा ही राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है तथा अपनी उपलब्धियों को हम भारत माता के चरण कमलों में समर्पित कर सकते हैं।

हम आशा करते हैं कि ये शब्द सदा ही हमारे कानों में गूंजत रहेंगे,'संगठन द्वारा संघर्ष' तथा 'संघर्ष द्वारा संगठन' और संगठन व संघर्ष दोनों से राष्ट्र निर्माण कार्य में समर्पित हों' यही हमारी कामना है।

प्रिय भाइयो व बहनों ! आइये, हम आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिये। हमारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। हमारे दृढ़ संकल्प व निश्चय से ही समस्त कठिनाइयां व बाधायें समाप्त हो जायेंगी।

परिशिष्ट क्र० १

वर्ष १९८० तक भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियनें व सदस्य संख्या

क्र०	प्रदेश	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
१	जम्मू कश्मीर	१७	५७७५
२	हिमांचल	१९	१८१८६
३	पंजाब	१६८	९५०००
४	चण्डीगढ़	१७	३८८७
५	राजस्थान	१५०	१२१२२९
६	हरियाना	७३	३६३१०
७	दिल्ली	११५	४१९२०६
८	उत्तर प्रदेश	३५२	२७२६६५
९	बिहार	८१	१८८२८४
१०	बंगाल	१३८	१०२१३०
११	आसाम	१२	७०११२
१२	त्रिपुरा	१	२०००
१३	नागालैण्ड	१	११५
१४	उड़ीसा	१७	८२७१
१५	मध्य प्रदेश	१७७	९८४४०
१६	विदर्भ	४७	७६४५०
१७	महाराष्ट्र	१५४	१३५६८५
१८	गुजरात	३७	१८०००
१९	आन्ध्र	७४	५३२१२
२०	कर्नाटक	८१	४२१२८
२१	तामिलनाडु	८	३१३२५
२२	केरल	३६	७५००
	योग =	१७७५	१८०५९१०

परिशिष्ट क्र० २

वर्ष १९८० तक अ० भा० औद्योगिक महासंघों की यूनियनें तथा सदस्य संख्या

क्र०	औद्योगिक महासंघ	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
१	अ० भा० विद्युत मजदूर संघ	५१	११८८९३
२	अ० भा० इन्जीनियरिंग मजदूर संघ	१८८	१९१५८४
३	अ० भा० इस्पात मजदूर संघ	८	२५०००
४	भारतीय जूट मजदूर संघ	३१	३१८५३
५	भारतीय खदान मजदूर संघ	३७	९३८२२
६	भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ	६५	१००१०३
७	भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ	५१	५२०००
८	भारतीय रेलवे मजदूर संघ	१३	३६००००
९	भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ	८५	४०२००
१०	भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ	१६६	१५८२२५
११	नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेन्स वर्कर्स	३५	९१०००
१२	नेशनल आर्गनाइजेशन आफ जनरल इन्स्योरेंस वर्कर्स	३	९५६
१३	नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स	~~८०~~ ६६	[illegible]००००
१४	नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स	८	६०००
१५	अ० भा० स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ	१३१	३७६४२
१६	अ० भा० गैर शिक्षक कर्मचारी संघ	७	१२०००
१७	अ० भा० सीमेंट मजदूर संघ	१८	२१०००
१८	अ० भा० खेतिहर मजदूर महासंघ	२८	३८७७८
१९	भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ	८	७३३३
२०	भारतीय डाक तार कर्मचारी महासंघ	१२	२६४८३४
	योग =	१०४४	~~१६,४१,२२३~~ १६५११९०

इनके अतिरिक्त दो सहयोगी केन्द्रीय महासंघों की निम्नाङ्कित सदस्यता है—

१— गवर्नमेण्ट इम्प्लाइज नेशनल कान्फीडरेशन (राज्य तथा केन्द्र)—११०००००

२— गवर्नमेन्ट इम्पलाइज नेशनल फोरम (राज्य तथा केन्द्र)—३०३६८३

निम्नांकित केन्द्रीय औद्योगिक महासंघों के विधिवत स्थापित करने का प्रयास प्रारम्भ है—

१— अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ

२— अखिल भारतीय स्वास्थ्य, चिकित्सा व परिवार कल्याण मजदूर संघ

३— भारतीय फर्टीलाइजर मजदूर संघ

४— अ० भा० पब्लिक अन्डर टेकिंग मजदूर संघ

५— अ० भा० मुद्रणालय मजदूर संघ

परिशिष्ट क्र० ३

समाचार पत्रों की तालिका

क्र०	समाचार पत्र का नाम	भाषा	पता
१	हिम मजदूर	हिन्दी पाक्षिक	भारतीय मजदूर संघ, जेल रोड मण्डी (हिमांचल) १७५००१
२	मजदूर भारती	मलयालम मासिक	भारतीय मजदूर संघ टी० डी० रोड, इर्नाकुलम कोचीन (केरल) ६८२०११
३	भारतीय मजदूर संघ समाचार	हिन्दी मासिक	भारतीय मजदूर संघ २, नवीन मार्केट, कानपुर (उत्तर प्रदेश) २०८००१
४	भारतीय मजदूर क्रानिकल	हिन्दी पाक्षिक	४४/२६ दक्षिण तात्याटोपे नगर भोपाल
५	भारतीय मजदूर क्रानिकल	अंग्रेजी पाक्षिक	४४/२६ दक्षिण तात्याटोपे नगर भोपाल
६	श्रमधन	मराठी पाक्षिक	भारतीय मजदूर संघ २६७, भवानी रोड, सतारा
७	बिजली क्रानिकल	हिन्दी मासिक	१६ मल्हारगंज स्ट्रीट क्र०५ इन्दौर—२
८	वाहतुक वार्ता	मराठी मासिक	महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशन ब्यूटी बिल्डिंग के सामने, सीतावर्डी, नागपुर
९	कामगार एकता	मराठी पाक्षिक	बुलढाना
१०	भजदूर वार्ता	मराठी पाक्षिक	१८५ शनिवार पेठ पूना, ४११०३०
११	मजदूर चेतना	गुजराती मासिक	भारतीय मजदूर संघ, दीवचेम्बर देवरभाई रोड, राजकोट ३६०००१
१२	मजदूर संवाद	बंगाली मसिक	भारतीय मजदूर संघ, १० किरणशंकर राय रोड, कलकत्ता ७००००१
१३	मजदूर उद्घोष	हिन्दी मासिक	भारतीय मजदूर संघ ६/२२ आर० ब्लाक, पटना ८००००१
१४	डाक तार महासंघ	अंग्रेजी मासिक	टी–१५ अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली
१५	संचार वाणी	अंग्रेजी मासिक	टी–१५ अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली
१६	टेलीटेक	अंग्रेजी मासिक	३१२ लालकुर्ती बाजार, अम्बाला छावनी (हरियाना)

परिशिष्ट क्रं० ४

जयपुर अधिवेशन के पश्चात विभिन्न त्रिदलीय समितियों, गोष्ठियों, परामर्शदात्री समितियों चर्चाओं तथा वर्गों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची

क्र०	समितियों आदि के नाम	तिथि व स्थान	प्रतिनिधियों के नाम
१–अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ६४वीं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	जेनेवा ७ से २८ जून ७८	श्री जी० प्रभाकर
२–इटली टूरिन प्रशिक्षण (मेथोडालाजी फार ट्रेड इंसपेक्टर्स) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थायी वित्त योजना के अर्न्तगत	इटली २२ जनवरी से १३ अप्रैल,७८	श्री रामप्रसाद पारिख (नांदेड़)
३–अमेरिकी ट्रेड यूनियन आन्दोलन की गतिविधि कार्यकलाप व संगठन को देखने हेतु एक मास (अमेरिकी निमंत्रण पर)	अमेरिका	श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी
४–अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ६५ वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	जेनेवा ६ से २७ जून, ७९	श्री जी० प्रभाकर
५–प्रशिक्षण मेथोडालाजी पर ट्रेड यूनियन इन्सपेक्टर्स कोर्स की फेलोशिप	टूरीन ७ जनवरी से २८ मार्च, ८०	श्री बैजनाथ राय (कलकत्ता)
६–भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की संयुक्त स्थायी समिति	नई दिल्ली	श्री ओम प्रकाश अग्घी
७–वर्ष १९७७ की पुरस्कार प्रदान करने हेतु निर्णायक समिति	नई दिल्ली	श्री ओम प्रकाश अग्घी
८–ग्रामीण असंगठित मजदूरों की श्रम मन्त्रालय की केन्द्रीय स्थायी समिति	नई दिल्ली	श्री एम० जी० डोंगरे (बुलढ़ाना)

क्र०	समितियों आदि के नाम	तिथि व स्थान	प्रतिनिधियों के नाम
९—कोयला खदान की संयुक्त द्वि-पक्षीय समिति		नई दिल्ली	(१) श्री टी० सी० जुमड़े (भोपाल) (२) श्री बनारसी सिंह आजाद (उखड़ा)
१०—१९७८ से ८० तक की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद		१५ मार्च, ७८ नई दिल्ली	श्री घनश्यामदास गुप्त (शामली)
११—नेशनल लेवर इन्स्टीच्यूट की जनरल कौन्सिल		२० मार्च ७९ नई दिल्ली	श्री जी० के० आठवले
१२—खेतिहर मजदूरों हेतु केन्द्रीय कानून की उपसमिति		नई दिल्ली	श्री एम० जी० डोंगरे (बुलढाना)
१३—नेशनल सेफ्टी कौन्सिल बोर्ड आफ गवर्नस		नई दिल्ली	श्री ओमप्रकाश अग्वी
१४ कोयला उद्योग से सम्बन्धित उत्पादन वृद्धि, प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये ऊर्जा मंत्रालय की बैठक		नई दिल्ली १२ जुलाई ७८	श्री टी० सी० जुमड़े (भोपाल)
१५—कोयला उद्योग से सम्बन्धित कतिपय मसलों पर केन्द्रीय श्रम संगठनों से ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राय मशविरा		नई दिल्ली ११ अगस्त तथा १२ सितम्बर, १९७८	(१) श्री टी०सी० जुमड़े (२) श्री श्यामसुन्दर गुप्त (चिरमिरी, मध्य प्रदेश)
१६—सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन पुनरीक्षण हेतु मार्ग निर्देशक समिति		नई दिल्ली	श्री महिनारायण झा (हरिद्वार)
१७—१९७८-८३ की पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर श्रमिक नेताओं व विशेषज्ञों से योजना आयोग द्वारा राय मशविरा		नई दिल्ली २३ नवम्बर, ७८	(१) श्री जी० प्रभाकर (२) श्री राजकृष्ण भक्त

क्र०	समितियों आदि के नाम	तिथि व स्थान	प्रतिनिधियों के नाम
१८–	यन० टी० सी० की समस्याओं के सम्बन्ध में स्टडी ग्रुप		(१) श्री विश्वनाथ (२) श्री अर्जुन (३) श्री सतम (बम्बई)
१९–	'समान कार्य के लिये समान पारिश्रमिक' विषयक समिति	नई दिल्ली	श्रीमती उज्वला अरोरा (जयपर)
२०–	करेन्ट इयर्स इन्सटालमेन्ट आफ कम्पलसरी डिपोजिट्स अन्डर एडीशनल इमालूमेन्ट्स एक्ट १९७४ पर श्रम मंत्रालय द्वारा राय मशविरा	नई दिल्ली १ सितम्बर, ७९	श्री ओमप्रकाश अग्घी
२१–	सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित वेतन पुनरीक्षण व मंहगाई भत्ता आदि के बारे में श्रम मंत्रालय द्वारा वार्ता	नई दिल्ली १ सितम्बर, ७८	श्री ओमप्रकाश अग्घी
२२–	बहुद्देशीय निगमों की त्रिदलीय समिति	नई दिल्ली ११ अक्टूबर, ७९	श्री ओमप्रकाश अग्घी
२३–	संगठित व असंगठित क्षेत्र में बच्चों को रोजगार सम्बन्धी समस्याओं पर विचारार्थ समिति	नई दिल्ली ११ अक्टूबर, ७९	श्री हरीकृष्ण पाठक (नई दिल्ली)
२४–	हिन्दुस्तान स्टील वर्कर कन्सट्रक्शन लि० से सम्बन्धित श्रमिकों की समस्याओं का संयुक्त फोरम	कलकत्ता ९ नवम्बर, ७९	(१) श्री रामजीदास शर्मा (कलकत्ता) (२) श्री सरोजकुमार मित्रा (कटक)
२५–	बोनस, औद्योगिक सम्बन्ध तथा वर्तमान अन्य मजदूर समस्याओं पर श्रम मन्त्री की वार्ता	नई दिल्ली ८ फरवरी, ८०	(१) श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी (२) रामनरेश सिंह (३) श्री ओमप्रकाश अग्घी
२६–	केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधित्व तथा अन्य महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं पर श्रम मन्त्री की वार्ता	नई दिल्ली ३० जून, ८०	(१) रामनरेश सिंह (२) श्री ओमप्रकाश अग्घी

क्र० समितियों आदि के नाम	तिथि व स्थान	प्रतिनिधियों के नाम
२७—वर्तमान आर्थिक स्थिति पर प्रधान मन्त्री की श्रमिक प्रतिनिधियों से वार्ता	नई दिल्ली १ जुलाई, ८०	रामनरेश सिंह
२८—केन्द्रीय योजना मन्त्री द्वारा बुलायी गयी छठीं योजना पर राय मशविरा	नई दिल्ली २५ सितम्बर, ८०	(१) रामनरेश सिंह (२) श्री ओमप्रकाश अग्घी
२९—बाल श्रम पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	नई दिल्ली	श्री गोविन्दराव आठवले
३०—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध की १५वीं सभा	नई दिल्ली १५ अक्टूबर, ८०	श्री जी प्रभाकर
३१—बीड़ी व सिगार वर्कर्स कन्डीशन आफ इम्पलायमेन्ट एक्ट १९६६ तथा लीविंग एण्ड वर्किंग कन्डीशन्स पर त्रिदलीय सम्मेलन	नई दिल्ली २१ जन०, ८१	श्री रामप्रसाद पारिख (नान्देड़)
३२—सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों की साझेदारी उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिक सम्बन्ध पर वर्किंग ग्रुप	नई दिल्ली अप्रैल से अगस्त, ७८ (१० दिन)	श्री यच०एन०विश्वास (नांगल)
३३—फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम	नई दिल्ली १-२ मई, ७८	(१) श्री राजकृष्ण भक्त (१) श्री जी० प्रभाकर (३) श्री ओमप्रकाश अग्घी
३४—धनवाद में २७ व २८ नवम्बर, ७६ को सम्पन्न हुये खदानों में सुरक्षा सम्बन्धी विषय के सम्मेलन के निर्णयों पर राय मशविरा	नई दिल्ली १८ मई, ७८	(१) श्री बनारसी सिंह आजाद (उखड़ा) (२) श्री टी०सी० जुमड़े (भोपाल)

क्र०	समितियों आदि के नाम	तिथि व स्थान	प्रतिनिधियों के नाम
३५–	थर्ड सी० ओ०आई०/ आई०एल० ओ०/यू० एम० एफ० पी० ए० थर्ड रीजनल लेबर मैनेजमेन्ट सेमिनार फार पापुलेशन इजुकेशन एण्ड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग फार दी आर्गनाइज्ड सेक्टर (वेस्टर्न रीजन)	भोपाल ५ से ८ जुलाई, ७८	(१) श्री ए० एस० करम्बेलकर (बम्बई) (२) श्री सुन्दर सिंह शक्रवार (छिन्दवाड़ा)
३६–	फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम त्रिदलीय समिति	नई दिल्ली १२ जुलाई, ७८	रामनरेश सिंह
३७–	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ट्रेनिंग और इम्पलायमेन्ट पर भोपाल में सेमिनार	६, ७ नवम्बर, ७८	श्री गोविन्दराव आठवले
३८–	आई० एल० ओ० सेमिनार फार ट्रेड यूनियन लीडर्स आन रूरल वर्कर्स आर्गनाइजेशन इन इण्डिया	वाराणसी २० से २४ नवम्बर, ७८	(१) श्री एम० जी० (डोंगरे) (२) श्री रामप्रकाश मिश्र
३९–	जी० ओ० आई०/आई० एल० ओ०/यू० एन० एफ० पी० ए० फोर्थ रीजनल लेवर मैनेजमेन्ट सेमिनार फार पापुलेशन इजुकेशन फैमिली वेलफेयर प्लानिंग फार दी आर्गनाइज्ड सेक्टर्स इस्टर्न रीजन	भुवनेश्वर ५ से ८ फरवरी, ७९	(१) श्री सरोजकुमार मिश्रा (कटक) (२) श्री रामदेव प्रसाद (पटना)
४०–	आई० एल० ओ०/नारवे एशियन रीजनल सेमिनार आन दी रोल आफ ट्रेड यूनियन्स इन सोशल सेकूरीटी।	त्रिवेन्द्रम २१ मार्च से ३ अप्रैल, ७९	श्री जी० प्रभाकर
४१–	ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का ग्रामीण मजदूरों की दृष्टि से प्रथम परिसंवाद	दिल्ली २६ से २९ मार्च, ७९	(१) श्री० एम० जी० डोंगरे (बुलढाना) (२) श्री कृष्णचन्द्र चतुर्वेदी (मामा) (कोटा)

क्र०	समितियों आदि के नाम	तिथि व स्थान	प्रतिनिधियों के नाम
४२–	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा केन्द्र द्वारा आयोजित एन० एम० जोशी तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन के तहद 'ट्रेड यूनियन एकता' विषय पर परिसंवाद	बम्बई १० से १२ अप्रैल, ८०	श्री मनहर मेहता (बम्बई)
४३–	मिनिमम वेज (सेन्ट्रल) एडवाइजरी बोर्ड	—	(१) श्री रमन गिरधर शाह (बम्बई) (२) श्री टी० सी० जुमड़े (भूपाल)
४४	केन्द्रीय श्रम संगठनों की द्विपक्षीय वार्ता समिति	नयी दिल्ली ६ फरवरी, ८१	(१) श्री रामनरेश सिंह (२) श्री ओमप्रकाश आग्वी
४५–	**कमेटीज फार डाइरेक्शन—**		
	(१) सेन्ट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट	कलकत्ता	श्री स्वपन सेन गुप्ता (कलकत्ता)
	(२) फोरमैन ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट	बंगलौर	श्री सरोथराव (बंगलौर)
	(३) एडवान्स्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट	मद्रास	श्री के० महालिंगम् (मद्रास)
४६–	हाई पावर्ड इक्सपर्ट कमेटी आन ट्रेनिंग अन्डर दी क्राफ्टमैन एण्ड एप्रन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम्स	कलकत्ता २६ जून, ७८ व ११ अक्टूबर, ७९	श्री बैजनाथ राय (कलकत्ता)

श्रमिक शिक्षा केन्द्र द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित अभ्यास वर्ग में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि

क्र०	पाठ्यक्रम (विषय) का नाम	भाग लेने वाले प्रतिनिधि
१	ट्रेड यूनियन लीडर शिप	(१) श्री पी० ईश्वर भट्ट, करसगड (केरल) (२) श्री बलबीर कुमार शर्मा, (हिमांचल) (३) श्री बसन्त राव देशपाण्डेय, अमरावती (विदर्भ)
२	लाइब्रेरी प्रशासन	(१) श्री सुरेश नारायण सोले, (नागपुर) (२) श्री धर्मबीर शास्त्री, (चन्दीगढ़)
३	ट्रेड यूनियन जरनलिज्म	(१) श्री सुखदेव प्र० मिश्र, (कानपुर) (२) श्री शक्तिशेखर दास, (कलकत्ता)
४	वीमन ट्रेड यूनियन फंक्शनरीज	कुमारी पद्मा पाठक, (बुलढाना)
५	लाइब्रेरी प्रशासन	(१) श्री सी० ए० श्री निवास शास्त्री, (बंगलौर) (२) श्री वी० सी० चन्द्रमौलि, (हैदराबाद) (३) श्री जयन्त गंगाधर, (नागपुर)
६	ट्रेड यूनियन जरनलिज्म	(१) श्री ऋषिराज शर्मा, (जयपुर) (२) श्री रमेशचन्द्र गुप्त, (जम्मू)
७	इकनामिक इजुकेशन	(१) श्री सुधाकर भट्ट, (बंगलौर) (२) श्री अमर किशोर झा, धुर्वा (रांची) (३) श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा, (जम्मू) (४) श्री सुरेश शर्मा, (भोपाल)
८	वीमन ट्रेड यूनियन फंक्शनरीज	(१) श्रीमती शारदा आचार, (मंगलोर) (२) श्रीमती जुपुटी हिमावती (गुन्टूर) (३) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, (हरिद्वार) (४) श्रीमती गीता सिंह, हरिद्वार) (५) कुमारी जशवीर कौर, (दिल्ली) (६) श्रीमती एस० एल० सिंह, (नई दिल्ली)
९	ट्रेड यूनियन जरनलिज्म	(१) श्री सर्वेशचन्द्र द्विवेदी, (कानपुर) (२) श्री ओंकार नाथ शर्मा, (जोधपुर)
१०	मेनटेनेन्स आफ एकाउन्ट्स एण्ड सेक्रेटेरियल वर्क	३१ शिक्षार्थी प्रतिनिधि सम्मिलित (पूरा वर्ग अपने ही प्रतिनिधियों से सम्पन्न हुआ)।

केन्द्रीय कार्य समिति की बैठकें

१	बंगलौर	२६, २७ सितम्बर, १९७८
२	नई दिल्ली	१९, २० नवम्बर, १९७८
३	भोपाल	१९, २० फरवरी, १९७९
४	चण्डीगढ़	१८, १९ जून, १९७९
५	वाराणसी	२८, २९ अक्टूबर, १९७९
६	पूना	१८ जनवरी, १९८०
७	कटक	२८, २९ अप्रैल, १९८०
८	टाटानगर	८, ९ सितम्बर, १९८०

वन्दे मातरम्

रामनरेश सिंह